कमल संदेश

वर्ष-16, अंक-16 16-31 अगस्त, 2021 (पाक्षिक) ₹20

किसान परिवारों के खातों में सीधे भेजी गयी 19,500 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का उत्तर प्रदेश प्रवास

'भाजपा गरीब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े, वंचित, युवा और महिलाओं के कल्याण के लिए काम कर रही है'

पणजी में गोवा राज्य कैबिनेट मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र की एक संगठनात्मक बैठक को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा और साथ में अन्य वरिष्ठ भाजपा नेतागण

आगरा (उत्तर प्रदेश) में 'चिकित्सक (कोरोना योद्धा) सम्मेलन' को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

नई दिल्ली में झारखंड के सांसदों की बैठक की अध्यक्षता करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) में रोप-वे का उद्घाटन व 'मां विंध्यवासिनी' कॉरिडोर की आधारशिला रखने के बाद जनाभिवादन स्वीकार करते केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

कारगिल विजय दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सह संपादक
संजीव कुमार सिन्हा
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
भोला राय

डिजिटल मीडिया
राजीव कुमार
विपुल शर्मा

सदस्यता एवं वितरण
सतीश कुमार

इ-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
फोन: 011-23381428, फैक्स: 011-23387887
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 **'योगी आदित्यनाथजी के नेतृत्व में राज्य में चहुंओर विकास की नई कहानी लिखी जा रही है'**

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 7 अगस्त, 2021 को लखनऊ (उत्तर प्रदेश) के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश के 'जिला पंचायत अध्यक्ष एवं ब्लॉक प्रमुख' सम्मेलन को संबोधित किया और प्रधानमंत्री...

08 **'एक राजनीतिक पार्टी होने के साथ-साथ हमारा मानवीय पक्ष भी रहा है'**

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 28 जुलाई, 2021 को पार्टी के...

11 **9.75 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के खातों में सीधे भेजी गयी 19,500 करोड़ रुपये...**

गत नौ अगस्त को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम...

24 **उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज एक विशाल संकुल बनाकर आगे बढ़ेगा: अमित शाह**

गत एक अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट...

28 **चिकित्सा शिक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत मिलेगा आरक्षण**

गत 29 जुलाई, 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में स्वास्थ्य...

वैचारिकी

समाज और विचारधारा / **दीनदयाल उपाध्याय** 14

श्रद्धांजलि

भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी 16

साक्षात्कार

वर्तमान में हम भारत के इतिहास में महिला सशक्तिकरण का स्वर्ण युग देख रहे हैं: **वानथी श्रीनिवासन** 20

लेख

जन आशीर्वाद यात्रा जनता व सरकार के बीच अद्भुत पहल / **सुनील देवधर** 18

मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल ई-रुपी से जनता को सीधा लाभ / **गोपाल कृष्ण अग्रवाल** 22

अन्य

'गोवा आज भाजपा सरकार के नेतृत्व में देश का एक अग्रणी राज्य है' 09

'मोदी सरकार के लिए सामाजिक न्याय एक प्रतिबद्धता है' 10

'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' शुरू होने के बाद लाभार्थियों को पहले की तुलना में लगभग दोगुना राशन मिल रहा है: नरेन्द्र मोदी 12

बसवराज बोम्मई बने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री 17

स्वदेशी विमानवाहक पोत 'विक्रांत' के समुद्री परीक्षणों की शुरुआत 25

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा की पहल राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक प्रशिक्षण अभियान 31

'मन की बात' 33

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, प्लॉट नं.-8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.)-201306 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

सोशल मीडिया से

नरेन्द्र मोदी
आने वाले 25 साल में देश की कृषि को समृद्ध करने में छोटे किसानों की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। इसलिए, देश की कृषि नीतियों में इन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

जगत प्रकाश नड्डा
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी के नेतृत्व में हमारी सरकार दलितों व वंचितों को मुख्यधारा से जोड़ने, संवैधानिक अधिकार, सामाजिक न्याय व सभी को समान अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है।

अमित शाह
देश के सर्वोच्च खेल सम्मान 'खेल रत्न अवार्ड' को देश के महानतम खिलाड़ी मेजर ध्यान चंद जी के नाम पर रखना उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। यह खेल जगत से जुड़े हर व्यक्ति के लिए एक गर्व का निर्णय है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी का सभी देशवासियों की ओर से अभिनंदन करता हूं।

राजनाथ सिंह
'भारत छोड़ो आंदोलन' की वर्षगांठ के अवसर पर मैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण एवं नमन करता हूं। उनके संघर्ष की कहानियां आज भी जनमानस के हृदयपटल पर अंकित हैं। देश को दासता से मुक्ति दिलाने वाले इन सच्चे सपूतों के प्रति पुनः कोटि-कोटि नमन!

बी.एल. संतोष
श्री बजरंग पुनिया को टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती की 65 किग्रा स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर बधाई। #Cheer4India

नितिन गडकरी
'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' के तहत वितरित किए जा रहे प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न कोविड-19 से प्रभावित लोगों के लिए बड़ी राहत है।

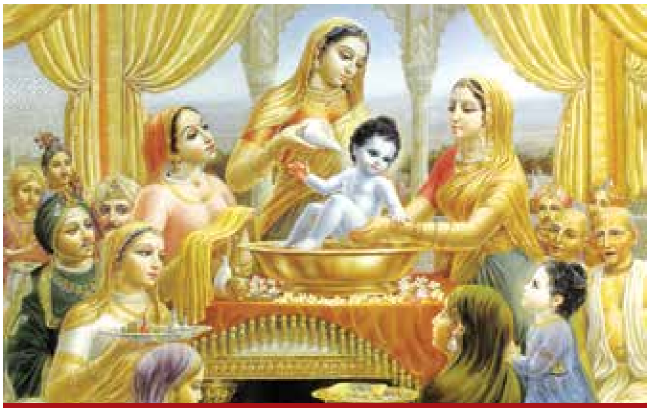

कमल संदेश परिवार की ओर से सुधी पाठकों को **श्रीकृष्ण जन्माष्टमी** (30 अगस्त) की हार्दिक शुभकामनाएं!

सेवा की नई गाथा

देश में 50 करोड़ से अधिक टीके लगने के साथ ही भारत ने कोविड-19 महामारी के विरुद्ध लड़ाई में एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया। साथ ही, 'सिंगल डोज' 'जॉनसन एंड जॉनसन' टीके को स्वीकृति मिलने से देश में टीकाकरण अभियान और भी अधिक तेज होने की संभावना है। एक ओर जहां इस महामारी से पूरा विश्व प्रभावित हुआ है, वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में चल रहे विश्व के सबसे बड़े एवं सबसे तेज टीकाकरण अभियान से व्यक्ति के जीवन की रक्षा करने का राष्ट्र का संकल्प और भी अधिक सुदृढ़ हुआ है। टीकाकरण अभियान से जहां हर व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं जीवन की रक्षा सुनिश्चित हो रही है, वहीं दूसरी ओर 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' से यह सुनिश्चित हुआ है कि देश में गरीब से गरीब व्यक्ति भी महामारी के इस दौर में भूखा न सोए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सुदृढ़ एवं करिश्माई नेतृत्व में भारत एक ऐसे देश के रूप में उभरा है जिसने कोविड-19 महामारी की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना तो किया ही है, साथ ही विश्व के दूसरे देशों के साथ उनके संकट की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा भी रहा है।

एक ऐतिहासिक निर्णय में मोदी सरकार ने देशभर के चिकित्सा महाविद्यालयों में अति पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया है। ध्यान देने योग्य है कि पिछले पांच वर्षों में मोदी सरकार ने देश में 179 नए चिकित्सा महाविद्यालय शुरू किए हैं, जिससे स्नातकोत्तर में 56 प्रतिशत तथा स्नातक शिक्षा में 80 प्रतिशत सीटों की बढ़ोतरी हुई है। एक ओर जहां मोदी सरकार की प्राथमिकता स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ कर उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने पर रही है, वहीं दूसरी ओर इसकी नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों में एक समरस एवं समावेशी समाज के निर्माण के सिद्धांत प्रमुखता से कार्यान्वित किए गए हैं। गरीबों, वंचितों, शोषितों एवं पीड़ितों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो मोदी सरकार अनु.जा., अनु.जन.जा., पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराकर राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में उन्हें महत्वपूर्ण भागीदार बना रही है। नए मंत्रिपरिषद् के विस्तार में पिछड़ा वर्ग के 27 मंत्री, अनु.जा. एवं अनु.जन.जा. के 20 मंत्री एवं 11 महिला मंत्री को शामिल करना 'नए भारत' की आकांक्षाओं को पूरा करने में हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित कर पूरे समाज को एकजुट करने का मोदी सरकार के संकल्प का परिचय देता है। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना, प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति का विस्तार के साथ-साथ गरीबों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों के लिए अनेक अभिनव योजनाओं से देशभर में नई आशा की किरण जगी है। परिणामतः देश का मेहनतकश गरीब अब पूरे राष्ट्र के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलने को तत्पर हैं।

> आज जब पूरा देश एकजुट होकर इस वैश्विक महामारी से लड़ रहा है, भाजपा कार्यकर्ता समर्पण एवं सेवा की नई गाथा लिख रहे हैं

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने एक नए अभियान का शुभारंभ किया है जिसके अंतर्गत पूरे देश में लाखों 'स्वास्थ्य स्वयंसेवक' प्रशिक्षित किए जाएंगे। ये 'स्वास्थ्य स्वयंसेवक' कोविड-19 महामारी की चुनौतियों का गांव-गांव में सामना करेंगे। ये न केवल लोगों की आवश्यकता पड़ने पर हर प्रकार की सेवा-सहायता करेंगे, बल्कि महामारी के प्रसार को रोकने के लिए प्रतिरक्षात्मक कदम भी उठाएंगे। ध्यान देने योग्य है कि पूरे देश में 'सेवा ही संगठन' अभियान के अंतर्गत करोड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोगों को राशन, फेसकवर, सैनिटाइजर एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं वितरित किया तथा संक्रमित एवं वरिष्ठ जनों की सेवा-सहायता में खड़े रहकर व्यापक राहत कार्य किए। इस कठिन दौर में जहां दूसरे राजनैतिक दलों ने स्वयं को घरों में बंद कर लिया तथा एक-दूसरे पर कीचड़ उछालने की तुच्छ राजनीति में लिप्त रहे, वहीं भाजपा कार्यकर्ता अपनी जान को दांव पर लगाकर निरंतर जनसेवा में लगे रहे तथा कोरोना योद्धाओं का मनोबल ऊंचा किया। आज जब पूरा देश एकजुट होकर इस वैश्विक महामारी से लड़ रहा है, भाजपा कार्यकर्ता समर्पण एवं सेवा की नई गाथा लिख रहे हैं। ■

shivshaktibakshi@kamalsandesh.org

जिला पंचायत अध्यक्ष एवं ब्लॉक प्रमुख सम्मेलन, उत्तर प्रदेश

योगी आदित्यनाथजी के नेतृत्व में राज्य में चहुंओर विकास की नई कहानी लिखी जा रही है: जगत प्रकाश नड्डा

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने उत्तर प्रदेश में 7 एवं 8 अगस्त, 2021 को दो दिवसीय संगठनात्मक प्रवास किया। पहले दिन उन्होंने लखनऊ में कई संगठनात्मक बैठकें कीं तथा दूसरे दिन आगरा में कई बैठकें कीं और कोरोना वॉरियर्स सम्मेलन को भी संबोधित किया

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 7 अगस्त, 2021 को लखनऊ (उत्तर प्रदेश) के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश के 'जिला पंचायत अध्यक्ष एवं ब्लॉक प्रमुख' सम्मेलन को संबोधित किया और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भाजपा की योगी आदित्यनाथ सरकार की जमकर सराहना की।

कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश भाजपा प्रभारी श्री राधा मोहन सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री बी.एल. संतोष, उप-मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य एवं श्री दिनेश शर्मा के साथ-साथ पार्टी के सभी नव-निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख उपस्थित थे। इससे पहले लखनऊ में अमौसी एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने श्री नड्डा का जोरदार स्वागत किया। हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुए जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में भाजपा को शानदार विजय मिली थी। भाजपा ने 826 ब्लॉक प्रमुखों में से 826 और 75 जिला पंचायतों में से 67 पर जीत का परचम लहराया था।

श्री नड्डा ने जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भाजपा की शानदार जीत पर पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि जिला परिषद और क्षेत्र पंचायत के नतीजों को हम प्रजातांत्रिक तरीके से देखें, तो ये पहला चरण है, जहां प्रजातंत्र सबसे ज्यादा मजबूती के साथ हमें देखने को मिलता है। यहां का चुनाव आप जीतकर आए हैं, आप सभी का मेरी और पार्टी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रजातंत्र में काम करने की संस्कृति को बदलकर रख दिया है। पहले एक प्रधानमंत्री थे जो कहते थे कि 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा ही नीचे पहुंचता है। आज हमें गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री 1 रुपया भेजते हैं, तो नीचे भी सीधे 1 रुपया ही पहुंचता है और वह भी सही लाभार्थियों तक पहुंचता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है गरीबों की भलाई करना और गांव, गरीब,

किसान, दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, युवा एवं महिलाओं के जीवन का उत्थान करना।

किसानों के भलाई के मुद्दे पर बोलते हुए श्री नड्डा ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्रीजी देश के सभी किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत हर वर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दे रहे हैं। इसके तहत अब तक 10 करोड़ से अधिक किसानों को लगभग 1.36 लाख करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में लगभग दो करोड़ किसानों को इसका लाभ मिला है।

उन्होंने कहा कि 2014 में उत्तर प्रदेश का बजट लगभग 2 लाख करोड़ रुपये था जो आज बढ़कर लगभग साढ़े पांच लाख करोड़ रुपये हो गया है। उत्तर प्रदेश की जीडीपी लगभग दो गुना से भी अधिक

उत्तर प्रदेश की विकास गाथा पर विस्तार से चर्चा करते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा -

- जन-धन योजना के माध्यम से देश भर में लगभग 40 करोड़ खाते खोले गए जिसमें से 7 करोड़ खाते उत्तर प्रदेश में खुले।
- देश भर में 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ जिसमें लगभग डेढ़ करोड़ शौचालयों का निर्माण उत्तर प्रदेश में हुआ।
- उज्ज्वला योजना के तहत देश के 8 करोड़ गरीब परिवार को गैस कनेक्शन मिला जबकि उत्तर प्रदेश के 2.54 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला।
- सौभाग्य योजना से घर-घर बिजली पहुंची है। देश भर में ढाई करोड़ से अधिक घरों में इस योजना के तहत बिजली पहुंची जबकि उत्तर प्रदेश के लगभग 80 लाख घर रौशन हुए।
- आयुष्मान भारत के तहत देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को सालाना पांच लाख रुपये तक का बीमा मिलता है। अब तक लगभग 2 करोड़ 54 लाख लाभार्थी इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 83 लाख लोगों ने इसका लाभ उठाया है।

बढ़कर 21.73 लाख करोड़ हो गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश आज देश में दूसरे स्थान पर है। हेल्थ केयर के सभी पैमानों पर उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ा है। पर कैपिटा इनकम में भी काफी वृद्धि हो रही है। आज उत्तर प्रदेश देश के पर्यटन सर्किट का मुख्य केंद्र बन कर उभर रहा है। आगरा, अयोध्या, मथुरा में पर्यटन सर्किट विकसित किये जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथजी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चहुंओर विकास की नई कहानी लिखी जा रही है।

श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश में राजनीति की संस्कृति को बदलते हुए विकास की संस्कृति विकसित की है जिसे योगी आदित्यनाथजी ने उत्तर प्रदेश की पावन धरा पर अक्षरशः उतारा है।

चिकित्सक (कोरोना वॉरियर्स) सम्मेलन, आगरा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने दूसरे दिन 8 अगस्त 2021 को आगरा (उत्तर प्रदेश) में 'चिकित्सक (कोरोना वॉरियर्स) सम्मलेन' को संबोधित किया। सम्मलेन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतन्त्र देव सिंह, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री बी.एल. संतोष एवं प्रदेश प्रभारी श्री राधामोहन सिंह भी उपस्थित थे। इससे पूर्व, श्री नड्डा ने आगरा में संगठनात्मक बैठक को भी संबोधित कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की।

श्री नड्डा ने कहा कि 2017 में लगभग 50,0000 लोगों की बीच हमने नई हेल्थ पॉलिसी पर चर्चाएं की थीं, 50,000 से ज्यादा इसपर सुझाव आए थे। उन सभी उचित सुझावों का समावेश करने के बाद, करीब 15 साल बाद, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, 2017 बनाई गयी। इस समग्र हेल्थ पॉलिसी में इस बात पर प्रमुखता से ध्यान दिया गया कि पहली कोशिश यह हो कि एक स्वस्थ आदमी बीमार ही न पड़े और यदि बीमार पड़ भी जाए तो बीमारी को ठीक करने के पहले बीमार के मन को ठीक करो। इस प्रकार, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, 2017 के तहत प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव और क्यूरोटिव (निवारक, प्रोत्साहक और उपचारात्मक) हेल्थ केयर का काम आरम्भ हुआ। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के तहत हमने तय किया कि देश में विद्यमान 1.5 लाख स्वास्थ्य उपकेंद्रों को 7-8 साल के भीतर हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र में बदल डालें जहां हर लोगों को एक प्रोफाइल तैयार हो सके, जिससे समय पर उनका उचित उपचार हो सके। यह गर्व की बात है आज अस्सी हजार स्वस्थ उपकेंद्रों पर हेल्थ एंड वेलनेस का काम शुरू हो चुका है और 2022 तक लक्ष्य है कि पूरे 1.5 लाख स्वास्थ्य उपकेंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र में तब्दील कर दिया जाएगा।

उन्होंने उत्तर प्रदेश की चिकित्सा सुविधा का जिक्र करते हुए कहा कि रायबरेली में 823 करोड़ की लागत से बनने वाली 610 बेड्स वाली एम्स तैयार हो रही है, गोरखपुर में 750 बेड्स की क्षमता वाली एम्स तैयार हो रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के आने के बाद उत्तर प्रदेश में अब तक 30 मेडिकल कॉलेज खोले जा चुके हैं और 1,550 एमबीबीएस सीटें बढ़ाई गई हैं। ■

राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान प्रशिक्षण कार्यक्रम

'एक राजनीतिक पार्टी होने के साथ-साथ हमारा मानवीय पक्ष भी रहा है'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 28 जुलाई, 2021 को पार्टी के नई दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित किया।

ज्ञात हो कि भारतीय जनता पार्टी ने 'अपना बूथ – कोरोना मुक्त' अभियान के तहत हर बूथ, हर गांव को कोरोना से मुक्त करने का अभियान शुरू किया है। इसके तहत हर बूथ पर भाजपा दो स्वास्थ्य स्वयंसेवक (एक पुरुष, एक महिला) तैयार कर रही है जो अपने-अपने बूथ के लोगों का कोविड देखभाल करेंगे। उनके पास ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर, एंटीबॉडी बूस्टर और रैपिड एंटीजेन टेस्ट किट भी उपलब्ध होंगे। वे न केवल लोगों को कोविड के प्रति जागरूक करेंगे बल्कि उन्हें कोविड से लड़ने में भी मदद करेंगे।

इस कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री तरुण चुघ, पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती डी. पुरंदेश्वरी, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री शिव प्रकाश और डॉ. राजीव बिंदल के साथ-साथ पार्टी पदाधिकारी और पार्टी के राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के स्वयंसेवक उपस्थित थे।

> हर बूथ पर भाजपा दो स्वास्थ्य स्वयंसेवक (एक पुरुष, एक महिला) तैयार कर रही है जो अपने-अपने बूथ के लोगों का कोविड देखभाल करेंगे

श्री नड्डा ने इस अवसर पर स्वास्थ्य स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने समय पर साहसिक और निर्णायक निर्णय लेते हुए देश को कोरोना के खिलाफ व्यापक लड़ाई के लिए तैयार किया। श्री नड्डा ने कहा कि कोविड की पहली और दूसरी लहर के दौरान भारतीय जनता पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता ने 'सेवा ही संगठन' के तहत अपनी जान जोखिम में डालकर मानवता की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया। कोविड संक्रमण के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने 50-60 करोड़ फूड पैकेट्स वितरित किये, लगभग 25 करोड़ फेस मास्क और 20 करोड़ सैनिटाइजर वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने न केवल प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने में मदद की बल्कि उनके लिए भोजन, वाहन और ठहरने का भी प्रबंध किया। बाकी राजनीतिक पार्टियों ने प्रवासी मजदूरों को भड़काने का काम किया लेकिन हमने उन्हें संभालने का काम किया।

उन्होंने कहा कि हम राजनीति में केवल चुनाव लड़ने के लिए नहीं हैं। एक राजनीतिक पार्टी होने के साथ-साथ हमारा मानवीय पक्ष भी रहा है। इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के लिए स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर रही है। हमें इस कार्यक्रम के जरिये देश के दो लाख गांवों तक पहुंचना है जिसके लिए हमने 4 लाख हेल्थ वालंटियर्स को प्रशिक्षित करने का बीड़ा उठाया है। अब तक लगभग 48 हजार से अधिक वालंटियर्स ने इस कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है।

श्री नड्डा ने कहा कि 'हमारा बूथ, कोरोना मुक्त' अभियान को सफल बनाने हेतु हमें इस ट्रेनिंग अभियान को सफल बनाना होगा। यह काम बहुत बड़ा है। 30 अगस्त तक मंडल स्तर तक यह प्रशिक्षण अभियान पूरा हो जाने की उम्मीद है। एक स्वास्थ्य स्वयंसेवक लोगों को कोविड से बचाव की जानकारी देने के साथ-साथ प्राथमिक लक्षणों की जांच में भी मदद करेंगे और कब रोगी को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ेगी, ये भी बताएंगे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने में भी सहयोग देंगे। हर स्वास्थ्य स्वयंसेवक के पास एक किट भी होगी जिसमें पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर, रैपिड एंटीजन टेस्ट किट और अन्य बूस्टर होंगे। ■

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का गोवा प्रवास

'गोवा आज भाजपा सरकार के नेतृत्व में देश का एक अग्रणी राज्य है'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा 24 जुलाई, 2021 से गोवा में दो दिवसीय प्रवास पर कई समीक्षा बैठकों में शामिल हुए और बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की।

पहले दिन श्री नड्डा गोवा के डाबोलिम हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। शाम को उन्होंने पार्टी के सांसदों और विधायकों से मुलाकात की और उन्हें संबोधित किया। उन्होंने पणजी में राज्य पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों और महासचिवों, मंडल अध्यक्षों, राज्य मोर्चा के अध्यक्षों और महासचिवों और मंडल पदाधिकारियों से मुलाकात की। श्री नड्डा ने पणजी में राज्य के कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की भी अध्यक्षता की।

अगले दिन 25 जुलाई को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 18वीं शताब्दी के श्रद्धेय श्री मंगेश मंदिर का दौरा किया, जो पोंडा तालुका की मोंगरी पहाड़ियों में पणजी से 20 किलोमीटर दूर है। इस दौरान उन्होंने भगवान शिव से समाज की भलाई के लिए प्रार्थना की। इसके बाद उन्होंने सुबह तपोभूमि मठ, कुंडेम का दौरा किया। श्री नड्डा ने वहां सद्गुरु ब्रह्मानंदाचार्य जी के साथ सुबह का नाश्ता किया। उन्होंने पणजी के डॉन बॉस्को स्कूल में कोविड टीकाकरण केंद्र का भी दौरा किया। उसी दिन श्री जगत प्रकाश नड्डा ने सुबह 11 बजे पणजी के बूथ संख्या 21 स्थित साईं मंदिर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की लोकप्रिय 'मन की बात' सुनी।

उन्होंने दोपहर में प्रदेश भाजपा की कोर टीम के साथ अहम बैठक की। पणजी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, "मैं गोवा में आयी अभूतपूर्व बाढ़ से जान गंवाने वाले लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से मृतकों के परिवार के सदस्यों को शक्ति देने की प्रार्थना करता हूं। हम सब उनका दुख बांटने में उनके साथ हैं।" उन्होंने कहा कि त्रासदी और संकट की इस घड़ी में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत के नेतृत्व में गोवा की भाजपा सरकार और पूरी भाजपा, गोवा की जनता की मदद के लिए उनके साथ खड़ी है। श्री नड्डा ने कहा कि गोवा में भारतीय जनता पार्टी अधिक मजबूत, प्रभावी और उत्तरदायी हुई है। मैंने राज्य के सभी विधायकों के साथ बातचीत की है और मैंने पाया है कि उनका मनोबल और उत्साह बहुत ऊंचा है और वे सभी राज्य के लोगों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भाजपा की प्रदेश इकाई पूरे समर्पण और सही दिशा में काम कर रही है।

> प्रति व्यक्ति आय के मामले में आज गोवा देश में अग्रणी राज्य है। इसी तरह, गोवा मानव विकास रैंकिंग में देश में तीसरे स्थान पर है जबकि आर्थिक विकास रैंकिंग में राज्य ने पिछले साढ़े चार वर्षों में अपनी रैंकिंग को बढ़ाते हुए सातवें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंच गया है

श्री नड्डा ने आगे कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में आज गोवा देश में अग्रणी राज्य है। इसी तरह, गोवा मानव विकास रैंकिंग में देश में तीसरे स्थान पर है जबकि आर्थिक विकास रैंकिंग में राज्य ने पिछले साढ़े चार वर्षों में अपनी रैंकिंग को बढ़ाते हुए सातवें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंच गया है। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' के सपने को साकार करने के लिए गोवा में मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मिशन 'स्वयंपूर्ण गोवा' शुरू किया है। ■

भाजपा, अनुसूचित जाति मोर्चा

'मोदी सरकार के लिए सामाजिक न्याय एक प्रतिबद्धता है'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 4 अगस्त, 2021 को नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में भारतीय जनता पार्टी, अनुसूचित जाति मोर्चा के तत्वावधान में अनुसूचित जाति समाज से आनेवाले केंद्रीय मंत्रियों के सम्मान में आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित किया और गांव, गरीब, किसान, दलित, पिछड़े, शोषित और वंचितों के उत्थान एवं कल्याण के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किये जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रमों की भूरि-भूरि सराहना की। इस कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री सी.टी. रवि, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री दुष्यंत गौतम, अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लाल सिंह आर्या, राष्ट्रीय संगठक श्री वी. सतीश, दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता और सभी अनु.जा. के केंद्रीय मंत्री उपस्थित थे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए बात करने वाले तो कई नेता हुए लेकिन उनके कल्याण के लिए इतनी छोटी अवधि में सबसे अधिक कार्य किसी ने किया है तो वे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी हैं। इसी तरह अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ों के कल्याण के लिए किसी ने जमीन पर काम किया है और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है तो वे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी हैं। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के विकास के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनको मुख्यधारा में लाने के लिए मोदी सरकार ने विशेष योजनाओं पर काम किया है।

उन्होंने कहा कि 2015 में 'समरसता दिवस' मनाने का काम मोदी सरकार ने किया। 'संविधान दिवस' मनाने की शुरुआत मोदी सरकार ने की। उन्होंने कहा कि हमारे 12 मंत्री अनुसूचित जाति से बने हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बने हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक समरसता के सिद्धान्त को आधार मानकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जहां अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग को संवैधानिक सुरक्षा देने की दिशा में उपाय किए। वहीं आवास, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के क्षेत्र में तमाम प्रावधान बनाकर दलित और शोषित समाज को सशक्त बनाने का काम किया।

उन्होंने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी सरकार के लिए सामाजिक न्याय सिर्फ कहने-सुनने की बात नहीं बल्कि एक प्रतिबद्धता है। गरीबों, वंचितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सम्मान और समान अधिकार दिलाना बाबासाहेब का सपना था, हम उन्हीं के सपनों को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। ■

भाजपा महिला मोर्चा

'केंद्रीय मंत्रिपरिषद् में महिलाओं को जितना प्रतिनिधित्व इस बार मिला है, उतना आज से पहले कभी नहीं हुआ'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 27 जुलाई, 2021 को पार्टी के नई दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की केंद्रीय मंत्रिपरिषद् में शामिल मातृशक्ति के अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित किया और भारत की मातृशक्ति की वंदना करते हुए परिवार, समाज और देश के नवनिर्माण में उनकी भूमिका की सराहना की। यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के तत्वावधान में आयोजित किया गया। केंद्रीय महिला मंत्रियों श्रीमती निर्मला सीतारमण, श्रीमती स्मृति ईरानी, श्रीमती मीनाक्षी लेखी, साध्वी निरंजन ज्योति, सुश्री शोभा कारंदलजे, श्रीमती दर्शना जरदोश, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, सुश्री प्रतिमा भौमिक, डॉ. भारती पवार और श्रीमती रेणुका सिंह को भाजपा महिला मोर्चा की ओर से सम्मानित किया गया।

भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती वानिती श्रीनिवासन ने महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देने और मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण स्थान देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का धन्यवाद किया और भाजपा में नारीशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा की भूरि-भूरि सराहना की। कार्यक्रम में महिला मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी एवं पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री दुष्यंत गौतम के साथ महिला मोर्चा की सभी पार्टी पदाधिकारी, महिला सांसद एवं वरिष्ठ मातृ शक्ति उपस्थित रहीं। कार्यक्रम को श्रीमती वानिती श्रीनिवासन के साथ-साथ केंद्रीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और श्रीमती स्मृति ईरानी ने भी संबोधित किया।

केंद्रीय महिला मंत्रियों का पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय में अभिनंदन करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि हमारी संस्कृति में मातृ शक्ति का सम्मान सदियों से है। जहां महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, वह परिवार हमेशा आगे बढ़ता है, उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जिस तरह से हर क्षेत्र में बेटियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है और अपने मंत्रिमंडल में नारी शक्ति को सम्मान दिया है, वह अभूतपूर्व और सराहनीय है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद् में महिलाओं को जितना प्रतिनिधित्व इस बार मिला है, उतना आज से पहले कभी नहीं हुआ। इस बार के मंत्रिमंडल में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिला है। श्री नड्डा ने कहा कि स्वच्छता अभियान और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने महिलाओं के जीवन के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ■

9.75 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के खातों में सीधे भेजी गयी 19,500 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर किसानों से अब तक की सबसे बड़ी खरीद, 1,70,000 करोड़ रुपये धान किसानों के खातों में और लगभग 85,000 करोड़ रुपये गेहूं किसानों के खातों में सीधे भेजे गए

गत नौ अगस्त को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत वित्तीय लाभ की अगली किस्त जारी की। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने किसान लाभार्थियों से बातचीत भी की। 19,500 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि, 9.75 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को अंतरित की गई। यह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत वित्तीय लाभ की 9वीं किस्त थी।

सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बुआई के मौसम के बारे में चर्चा की और यह उम्मीद जताई कि आज प्राप्त हुई राशि से किसानों को मदद मिलेगी। उन्होंने आज एक लाख करोड़ रुपये की निधि वाली किसान इंफ्रॉस्ट्रक्चर फंड की योजना के एक साल पूरे होने का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने शहद मिशन (मिशन हनी-बी) और नेफेड की दुकानों में जम्मू-कश्मीर के केसर बनाए जाने जैसी पहलों के बारे में चर्चा की। शहद मिशन की वजह से 700 करोड़ रुपये के शहद का निर्यात हुआ है, जिससे किसानों को अतिरिक्त आय हुई है।

आगामी 75वें स्वतंत्रता दिवस का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह गर्व का अवसर होने के साथ-साथ नए संकल्प लेने का भी एक अवसर है। उन्होंने कहा कि हमें इस अवसर का उपयोग यह तय करने के लिए करना होगा कि हम आने वाले 25 वर्षों में भारत को कहां देखना चाहते हैं। अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि 2047 में, जब देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, भारत की स्थिति को निर्धारित करने में हमारी कृषि और हमारे किसानों की बड़ी भूमिका होगी।

उन्होंने कहा कि चाहे खरीफ या रबी का सीजन रहा हो, सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर किसानों से अब तक की सबसे बड़ी खरीद की है। इससे करीब एक लाख 70 हजार करोड़ रुपये सीधे चावल का उत्पादन करने वाले किसानों के खाते में पहुंचे हैं और करीब 85,000 करोड़ रुपये सीधे गेहूं का उत्पादन करने वाले किसानों के खाते में गए हैं।

श्री मोदी ने इस बात की याद दिलाई कि जब कुछ साल पहले देश में दालों की कमी हुई थी, तो उन्होंने किसानों से दलहन का उत्पादन बढ़ाने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि इसके परिणामस्वरूप पिछले 6 वर्षों में देश में दालों के उत्पादन में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

प्रधानमंत्री ने खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए एक दृढ़संकल्प के रूप में 'राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम यानी एनएमईओ-ओपी' पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आज जब देश 'भारत छोड़ो आंदोलन' को स्मरण कर रहा है, इस ऐतिहासिक दिन पर यह दृढ़संकल्प हमें नई ऊर्जा से भर देता है। उन्होंने कहा कि 'राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम' मिशन के जरिए खाद्य तेल से जुड़ी समग्र व्यवस्था में 11,000 करोड़ रुपये से भी अधिक का निवेश किया जाएगा।

> **आज पहली बार भारत ने कृषि निर्यात के मामले में दुनिया के शीर्ष 10 देशों में स्वयं को शुमार किया है**

श्री मोदी ने कहा कि आज पहली बार भारत ने कृषि निर्यात के मामले में दुनिया के शीर्ष 10 देशों में स्वयं को शुमार किया है।

श्री मोदी ने कहा कि देश की कृषि नीतियों में अब छोटे किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इसी भावना के साथ पिछले कुछ वर्षों से इन छोटे किसानों को सुविधा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए अत्यंत गंभीरतापूर्वक प्रयास किए जा रहे हैं। 'पीएम किसान सम्मान निधि' के तहत अब तक किसानों को 1 लाख 60 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। इनमें से 1 लाख करोड़ रुपये महामारी के संकट काल के दौरान छोटे किसानों को अंतरित किए गए हैं। कोरोना काल के दौरान 2 करोड़ से भी अधिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए, जिनमें से अधिकांश छोटे किसानों को दिए गए। ■

'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' शुरू होने के बाद लाभार्थियों को पहले की तुलना में लगभग दोगुना राशन मिल रहा है: नरेन्द्र मोदी

महामारी के दौरान 80 करोड़ से अधिक लोगों को नि:शुल्क राशन मिल रहा है और इस पर लगभग 2 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए हैं

गत तीन अगस्त को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात में 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। योजना के बारे में और जागरूकता फैलाने के लिए राज्य में एक जन भागीदारी कार्यक्रम शुरू किया गया था।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि गुजरात में लाखों परिवारों को 'पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना' के तहत नि:शुल्क राशन मिल रहा है। यह नि:शुल्क राशन गरीबों के संकट को कम करता है और उन्हें आत्मविश्वास देता है। उन्होंने कहा कि गरीब नागरिकों को यह महसूस करना चाहिए कि कैसी भी आपदा आ जाए, देश सदैव उनके साथ है।

श्री मोदी ने कहा कि महामारी के दौरान 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक के खर्च के साथ 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक लाभार्थी को गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम, चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से निर्धारित खाद्यान्न के अलावा 5 किलो गेहूं और चावल मुफ्त दिया जा रहा है। यानी राशन कार्ड धारकों को इस योजना के शुरू होने से पहले की तुलना में लगभग दुगनी मात्रा में राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। यह योजना दिवाली तक जारी रहने वाली है।

> प्रत्येक लाभार्थी को गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम, चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से निर्धारित खाद्यान्न के अलावा 5 किलो गेहूं और चावल मुफ्त दिया जा रहा है

श्री मोदी ने कहा कि कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा। उन्होंने प्रवासी मजदूरों की देखभाल करने के लिए 'वन नेशन वन राशन कार्ड' पहल के उद्देश्य को पूरा करने के लिए गुजरात सरकार की प्रशंसा की।

श्री मोदी ने कहा कि आज देश बुनियादी ढांचे पर लाखों करोड़ रुपये खर्च कर रहा है, लेकिन साथ ही आम इंसान के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए 'ईज ऑफ लिविंग' के नए मानक भी स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज गरीबों के सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उन्हें सशक्त बनाया जा रहा है क्योंकि 2 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को घर मिला है, 10 करोड़ परिवारों को शौचालय मिला है। इसी तरह, जब वे जन-धन खाते के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में शामिल हो जाते हैं, तो वे सशक्त हो जाते हैं।

श्री मोदी ने कहा कि सशक्तिकरण के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, सुविधाएं और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए लगातार कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। आयुष्मान योजना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण, सड़कें, मुफ्त गैस और बिजली कनेक्शन, मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना जैसी योजनाएं गरीबों के सम्मानजनक जीवन को दिशा दे रही हैं और उनके सशक्तिकरण का माध्यम बन रही हैं।

उन्होंने भारत के ओलंपिक दल का उल्लेख करते हुए कहा कि इस बार ओलंपिक में भारत के अब तक के सबसे अधिक खिलाड़ियों ने क्वालीफाई किया है। याद रहे ये हमने 100 साल की सबसे बड़ी आपदा से जूझते हुए किया है। कई तो ऐसे खेल हैं जिनमें हमने पहली बार क्वालीफाई किया है। सिर्फ क्वालीफाई ही नहीं किया, बल्कि कड़ी टक्कर भी दे रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि पिछले साल लगभग 948 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया गया था जोकि कोविड-19 के दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सामान्य वर्ष में किए जाने वाले आवंटन से 50% अधिक है। 2020-21 के दौरान खाद्य सब्सिडी पर लगभग 2.84 लाख करोड़ रुपये का खर्च किया गया।

गुजरात में 3.3 करोड़ से अधिक पात्र लाभार्थियों को पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी राशि के खर्च के साथ 25.5 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किया गया। प्रवासी लाभार्थियों के लिए खाद्य सुरक्षा को और मजबूत करने के उद्देश्य से अब तक 33 राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों में 'एक राष्ट्र एक राशन' कार्ड योजना लागू की जा चुकी है। ■

जुलाई, 2021 में जीएसटी संग्रह 33 प्रतिशत बढ़कर 1,16,393 करोड़ रुपये हुआ

केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा एक अगस्त को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार जुलाई, 2021 में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 1,16,393 करोड़ रुपये रहा, जिसमें सीजीएसटी 22,197 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 28,541 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 57,864 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर संग्रहित 27,900 करोड़ रुपये सहित) और उपकर (सेस) 7,790 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर संग्रहित 815 करोड़ रुपये सहित) शामिल हैं। उपरोक्त आंकड़ों में 1 जुलाई, 2021 से 31 जुलाई, 2021 के बीच दाखिल जीएसटीआर-3बी रिटर्न से प्राप्त जीएसटी संग्रह के साथ-साथ आईजीएसटी और उस अवधि के लिए आयात से प्राप्त उपकर शामिल हैं।

1 जुलाई से 5 जुलाई, 2021 के बीच दाखिल 4,937 करोड़ रुपये के रिटर्न के लिए जीएसटी संग्रह को भी जून, 2021 के प्रेस नोट में जीएसटी संग्रह में शामिल किया गया था क्योंकि करदाताओं को छूट/कमी के रूप में विभिन्न राहत प्रदान किए गए थे। कोविड वैश्विक महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर 5 करोड़ रुपये तक के कुल कारोबार वाले करदाताओं को जून, 2021 महीने के लिए 15 दिनों की देरी से रिटर्न दाखिल करने के मामले में ब्याज पर छूट दी गई थी।

सरकार ने नियमित निपटान के रूप में आईजीएसटी से सीजीएसटी के लिए 28,087 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 24,100 करोड़ रुपये का निपटान किया है। जुलाई, 2021 में नियमित निपटान के बाद केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अर्जित कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 50,284 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 52,641 करोड़ रुपये है।

जुलाई, 2021 महीने के लिए राजस्व संग्रह पिछले साल के इसी महीने में संग्रहित हुए जीएसटी राजस्व के मुकाबले 33 प्रतिशत अधिक है। महीने के दौरान वस्तुओं के आयात से प्राप्त राजस्व 36 प्रतिशत अधिक रहा। जबकि घरेलू लेन-देन (सेवाओं के आयात सहित) से प्राप्त राजस्व पिछले साल के इसी महीने के दौरान इन स्रोतों से हासिल किए गए राजस्व के मुकाबले 32 प्रतिशत अधिक रहा।

जीएसटी संग्रह लगातार आठ महीने तक 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहने के बाद जून, 2021 में घटकर 1 लाख करोड़ रुपये के स्तर से नीचे आ गया था। जून, 2021 महीने के दौरान संग्रह काफी हद तक मई, 2021 से संबंधित था और मई, 2021 के दौरान अधिकतर राज्य/केंद्रशासित प्रदेश कोविड की दूसरी लहर के कारण पूर्ण अथवा आंशिक लॉकडाउन से जूझ रहे थे। कोविड संबंधी पाबंदियों में ढील के साथ ही जुलाई, 2021 के लिए जीएसटी संग्रह फिर से 1 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है। आने वाले महीनों में भी जीएसटी राजस्व संग्रह दमदार बने रहने की संभावना है। ■

भारत ने कोविड-19 टीकाकरण कवरेज में 50 करोड़ की अहम उपलब्धि हासिल की

भारत में कोविड-19 टीकाकरण कवरेज ने 6 अगस्त को 50 करोड़ की अहम उपलब्धि प्राप्त की। 7 अगस्त की सुबह सात बजे तक मिली अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल 58,08,344 सत्रों के जरिये टीके की कुल 50,10,09,609 खुराकें लगाई गईं। पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 49,55,138 खुराकें दी गईं। ब्योरा निम्न है:

स्वास्थ्य कर्मी	पहली खुराक	1,03,28,986
	दूसरी खुराक	79,53,278
अग्रिम पंक्ति के कर्मी	पहली खुराक	1,82,06,470
	दूसरी खुराक	1,16,55,584
18-44 वर्ष आयु वर्ग	पहली खुराक	17,26,01,639
	दूसरी खुराक	1,12,87,774
45-59 वर्ष आयु वर्ग	पहली खुराक	11,08,54,315
	दूसरी खुराक	4,19,57,311
60 वर्ष से अधिक स्वास्थ्य कर्मी	पहली खुराक	7,80,50,150
	दूसरी खुराक	3,81,14,102
योग		**50,10,09,609**

गौरतलब है कि सबके लिये कोविड-19 टीकाकरण का नया अध्याय 21 जून, 2021 को शुरू हुआ था। केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा बढ़ाने और इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिये कटिबद्ध है।

टीकाकरण का आंकड़ा 50 करोड़ से अधिक होने से कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई को जबरदस्त प्रोत्साहन: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 6 अगस्त को कहा कि टीकाकरण का आंकड़ा 50 करोड़ के पार पहुंच चुका है। भारत इन आंकड़ों को कहीं आगे बढ़ाते हुए यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हमारे नागरिकों को 'सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन' अभियान के तहत टीका लगाया जाए।

प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई को एक जबरदस्त प्रोत्साहन मिला है। टीकाकरण का आंकड़ा 50 करोड़ के पार पहुंच गया है। हम उम्मीद करते हैं कि इन आंकड़ों में और बढ़ोतरी होगी और हमारे नागरिकों के लिए 'सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन' अभियान के तहत टीकाकरण सुनिश्चित होगा। ■

समाज और विचारधारा

दीनदयाल उपाध्याय

यह तो स्पष्ट है कि समाजवाद के नाम से जो विषय चल रहा है तथा बहुत ही व्यापक और एक प्रकार से प्रभावी रूप से जिन कम्युनिस्ट देशों में इसका प्रसार होता दीख रहा है, उसमें व्यक्ति का और समाज का भी जैसा भला होना चाहिए, वैसा न होकर दूसरी ओर बुरा हाल है। यह बात अलग है कि देशों ने भौतिक दृष्टि से प्रगति कर ली होगी, लेकिन भौतिक प्रगति को समाजवादी पद्धति से जोड़ नहीं सकते। दुनिया के और भी देश हैं, जैसे अमरीका, उसने भी प्रगति की है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जिनमें अमरीका ने रूस से अधिक प्रगति की है। कुछ क्षेत्रों में रूस भी आगे निकल गया है। परंतु इन चीजों से विचारधारा के बारे में कोई निष्कर्ष निकालें तो वह गलत होगा। ये निष्कर्ष प्रचार की दृष्टि से निकाले जाते हैं।

पिछले दिनों एकाएक समाचार आया कि चीनी लोग एवरेस्ट पर चढ़ गए। कैसे चढ़ गए, इसका पता नहीं। वह पहले चढ़ रहे थे, इसकी भी खबर नहीं। फिर समाचार आया कि रात के एक बजे चढ़े। यह भी बताया गया कि उनकी यह विजय कम्युनिस्ट विचारधारा की विजय है। पर जानकार लोगों ने बताया कि इन समाचारों से ही पता लगता है कि ये ग़लत हैं। संभव भी हो तो विचारधारा के साथ तो इसको नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन लोग जोड़ते हैं। अभी अंतरिक्ष में यात्री को भेजा गया, फिर एक महिला को भेजा गया। उसके बारे में भी इसी प्रकार का विचार करते हैं। हमें वास्तविकता का गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसके पीछे तर्क या वैज्ञानिक ढंग के साधन नहीं। ये आधुनिक ढंग की रूढ़ियां हैं। जैसे छींक आ गई और लाभ नहीं हुआ तो धारणा हो जाती है कि छींक आ जाने से ही काम बिगड़ा है। यद्यपि इसमें कोई कारण-कार्य संबंध जोड़ा नहीं जा सकता। अनेक बार ऐसे भी हुआ होगा, जब छींक आने पर भी काम हुआ होगा, परंतु उसको कौन ध्यान में रखता है। एक जगह समुद्र में एक मंदिर था। उसके पुजारी ने मंदिर में उन सज्जनों की सूची बनाकर टांगी हुई थी, जिनका समुद्र यात्रा से मंदिर दर्शनार्थ आने पर कुछ न बिगड़ा हो अर्थात् जो डूबे नहीं तथा सकुशल लौट आए थे। इसका मन पर प्रभाव पड़ता है। एक बार एक दार्शनिक ने पुजारी से पूछा, "जो समुद्र यात्रा पर गए और डूब गए, उनका नाम नहीं लिखा। क्यों?" वे नाम तो उसके पास नहीं थे। इस प्रकार कुछ को छिपा लिया जाता है और कुछ को प्रकट किया जाता है और फिर गलत तरीके से उनमें कारण-कर्म भाव ढूंढ़ लिया जाता है। वैसे ही आज भी बहुत सी चीजें होती हैं।

हिटलर पिछली बार रूस के ख़िलाफ़ लड़ा और रूस जीत गया। इससे पहले वह जापान से हार गया था। तो एकमेव कारण कि रूस में साम्यवाद के कारण यह विजय हुई, ऐसा बताया जाने लगा। परंतु यदि यही तर्क लगाया जाए तो इंग्लैंड और अमरीका में तो साम्यवाद नहीं था। वे कैसे जीत गए और अमरीका वाले कह सकते हैं कि पिछली लड़ाई में अमरीका के आने के बाद जो हिटलर लड़ा तो वह हारा। तो यह सब हुआ अमरीका के पूंजीवाद के कारण। वह यह कह सकता है, पर इसमें भी कोई बल नहीं।

इन चीजों को हटाकर देखें तो पता लगेगा कि जो तथाकथित समाजवादी विचारधाराएं हैं, उनमें सबसे बड़ी ख़राबी है कि व्यक्ति के स्वरूप का और समाज के स्वरूप का जो सही ज्ञान होना चाहिए, वह उनके पास नहीं। इनमें भी लोग सब ताक़त अपने हाथ में लेकर बाक़ी के समाज को सुख-सुविधाओं से वंचित रखते हैं।

व्यक्ति जितना गुलाम पूंजीवादी यूरोप में था, संभवतः उससे अधिक गुलाम समाजवादी व्यवस्था में आज है। जितनी विषमताएं पूंजीवादी यूरोप में थीं, उससे अधिक विषमताएं समाजवादी यूरोप में हैं। विषमताओं का मापदंड बदल लिया गया है, लेकिन उससे अधिक विषमताएं लाई गई हैं

यह विचारधारा वहीं आकर खड़ी हो गई, जहां से इसने प्रारंभ किया था। व्यक्ति जितना गुलाम पूंजीवादी यूरोप में था, संभवतः उससे अधिक गुलाम समाजवादी व्यवस्था में आज है। जितनी विषमताएं पूंजीवादी यूरोप में थीं, उससे अधिक विषमताएं समाजवादी यूरोप में हैं। विषमताओं का मापदंड बदल लिया गया है, लेकिन उससे अधिक विषमताएं लाई गई हैं। विषमताओं का रूप बदल गया है। जैसे किसी को रुपया मासिक मिले और किसी को दस हजार रुपए तो यह कितनी बड़ी विषमता है। यह विषमता कम होनी चाहिए।

लेकिन यदि कोई दस हजार रुपए को यह रूप दे कि वेतन मिलेगा दो हजार शेष की बाक़ी चीजें मुफ्त, जैसे मकान, यातायात व्यय आदि। ये सब सरकार उसे मुफ्त देगी। नतीजा यही होगा कि विषमता शायद और बढ़ जाएगी। जब अंग्रेज यहां थे तो उनके वायसराय के एक्जीक्यूटिव के जो मेंबर थे, उनको साढ़े तीन या चार हजार तनख्वाह मिलती थी। इनकम टैक्स देने के बाद बाईस सौ–तेईस सौ रुपया बचता था। नई सरकार ने तनख्वाह को कम कर दिया। तनख्वाह दो हजार सात सौ पचास रुपए कर दी, लेकिन इनकम टैक्स माफ कर दिया। यदि आप देखेंगे कि ख्रुश्चेव पर कितना खर्च होता है तो अनुमान लगेगा कि उसकी तनख्वाह तो बढ़ी नहीं है। रूस में आज भी आय का अनुपात कुछ के कहने के अनुसार एक और दो सौ है। एक और अस्सी तो स्वीकार किया ही जाएगा।

वे शोषण समाप्त करने की बात कहते हैं। लेकिन आर्थिक क्षेत्र में शोषण समाप्त हुआ मान लिया जाए तो भी राजनीतिक दृष्टि से शोषण प्रारंभ कर दिया है कि मार्क्स ने जो अपने सारे निष्कर्ष निकाले थे तो उसमें 'सरप्लस वैल्यू' का सिद्धांत रखा था। उस अर्थव्यवस्था का आधार था जहां मंडी में मूल्य मांग और पूर्ति के संतुलन में तय होता है। फिर वास्तविक मूल्य क्या है, विनियम मूल्य क्या है। वह कितनी मात्रा में सही है। इन सबके पचड़े में मैं नहीं पड़ता। लेकिन कम्युनिस्ट देशों में 'मार्केट इकोनॉमी' नाम की चीज़ है ही नहीं। यह 'सरप्लस वैल्यू' मजदूर के पास जाती है, यह सच नहीं। यह आज राज्य के पास पहुंच जाती है और फिर कुछ व्यक्तियों के पास जाती है। आरंभ में शक्ति सुविधाएं कुछ हाथों में केंद्रित थीं। झगड़ा यहीं से प्रारंभ हुआ था कि शक्ति सुविधा कुछ हाथों में नहीं रहनी चाहिए, परंतु शक्ति कुछ ही हाथों में केंद्रित रही और बाक़ी के लोगों में अंतर नहीं आया; बल्कि जिन देशों में कम्युनिस्ट पद्धति नहीं, वहां अवश्य कुछ अंतर आया है।

जैसे व्यक्ति में भाव होते हैं, कर्म होते हैं, वैसे ही समाज की भावनाएं होती हैं, कर्म होते हैं। यह समाज के सभी व्यक्तियों के भावों या कर्मों का कुल जोड़ नहीं होता। इसके लिए गणित के अनुसार कैलकुलेशन का विचार नहीं किया जा सकता। यदि सबकी ताकत को जोड़ दिया जाए, जैसे राष्ट्रीय आय के लिए करते हैं कि प्रत्येक की आय का योग औसत निकाल लिया, वैसे समाज की शक्ति के लिए नहीं होगा

गलती यह है कि व्यक्ति और समाज का वास्तविक संबंध क्या है, स्वरूप क्या है, इसको लोग समझ नहीं पाए। समाज लोगों को मिलाकर बना है, यह ग़लत है। व्यक्तियों का समूह समाज नहीं, समाज की अपनी एक सत्ता है, जीवमान सत्ता है उतनी ही, जितनी एक प्राणी की होती है। प्राणी उसका अंग ज़रूर है लेकिन यह एक निर्जीव अंग जैसा नहीं, जैसे कि मोटर के पुर्जे होते हैं। यह वैसा ही है जैसा एक पूरा पेड़ होता है और उस पेड़ का एक पत्ता। पत्तों को मिलाकर पेड़ नहीं बनता। कोई यह कहेगा क्या कि हाथ, पैर, नाक, कान मिलाकर व्यक्ति बन जाता है? पुर्जों को मिलाकर मोटर बनेगी, पर मनुष्य शरीर के लिए ऐसा नहीं। 19वीं सदी में यही लोग बोलते थे कि जैसी मशीन है, शरीर भी वैसा ही है, जरा जटिल है। परंतु मशीन तो पुर्जे मिलाने से तैयार हो जाती है, शरीर नहीं हो पाता। क्योंकि उसमें प्राण फूंकना जरा टेढ़ा काम है। अभी तक किसी विज्ञानवेत्ता ने इसमें सफलता नहीं पाई।

पंचतंत्र में एक कहानी है कि कुछ पढ़नेवालों में एक को प्राण फूंकने की विद्या आती थी। उसने रास्ते में हड्डियों को देखा तो जोड़-जोड़कर उसका ढांचा खड़ा कर दिया। वह व्याघ्र था। जब प्राण फूंकने लगा तो उसका दूसरा साथी जो व्यावहारिक था, उसे मना करने लगा कि यह जीवित हो जाएगा तो तुझे खा जाएगा। उसके न मानने पर साथी तो पेड़ पर चढ़ गया और इधर जैसे ही व्याघ्र में जान आई। उसने सबसे पहले इसी का शिकार किया। यह कहानी केवल इसलिए है कि विद्या के साथ व्यावहारिकता भी चाहिए। व्यावहारिकता ने उसकी जान बचा दी। लेकिन यह तो एक कहानी है। वस्तुतः कोई प्राण फूंक नहीं सकता।

यह तो सत्य है कि शरीर में एक प्राण है। वास्तव में तभी इसके अंग-प्रत्यंग शरीर के सुख-दुःख को अनुभव करते हैं और इसी नाते सब काम करते हैं। समाज भी एक प्राणवान चीज है। समाज में भी वह गुण है, जो व्यक्ति के अंदर है। मनोवैज्ञानिक तो इसको स्वीकार भी करने लगे हैं कि समाज का मस्तिष्क होता है, जिसे group mind नाम दिया गया है। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से जो खून देखकर भी घबराएगा, वह भी राष्ट्र के लिए लड़ता है और फ़ौरन उत्साह से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे व्यक्ति में भाव होते हैं, कर्म होते हैं, वैसे ही समाज की भावनाएं होती हैं, कर्म होते हैं। यह समाज के सभी व्यक्तियों के भावों या कर्मों का कुल जोड़ नहीं होता। इसके लिए गणित के अनुसार कैलकुलेशन का विचार नहीं किया जा सकता। यदि सबकी ताकत को जोड़ दिया जाए, जैसे राष्ट्रीय आय के लिए करते हैं कि प्रत्येक की आय का योग औसत निकाल लिया, वैसे समाज की शक्ति के लिए नहीं होगा।

समाज की एक सत्ता मानने के बाद समाज की शक्ति का अंकन इस प्रकार नहीं होगा। वह भिन्न वस्तु है। हम उसके एक अंग हैं, परंतु वैसे ही हैं जैसे शरीर का हाथ से संबंध होता है। हम उसके एक अवयव हैं, परंतु हमारी एक स्वतंत्र सत्ता भी है। एक प्रकार के लोग तो यह मानते हैं कि समाज एक सत्ता है और मनुष्य एक पुर्जा मात्र है। दूसरे मानते हैं कि व्यक्ति सत्ता है, समाज समूह मात्र है। दोनों ग़लत हैं। व्यक्ति की अपनी सत्ता है, समाज की भी उतनी ही प्राणवान सत्ता है। दोनों एक-दूसरे से संबंधित हैं। हाथ शरीर से संबंधित है, परंतु हाथ की अपनी विशेषता है। प्रत्येक जीवाणु की अपनी सत्ता है। वह शरीर की सत्ता से मिलकर काम करते हैं। ■

(शेष अगले अंक में...)

(संघ शिक्षा वर्ग, बौद्धिक वर्ग, नई दिल्ली; जून २०, 1963)

भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी

(25 दिसंबर, 1924 – 16 अगस्त, 2018)

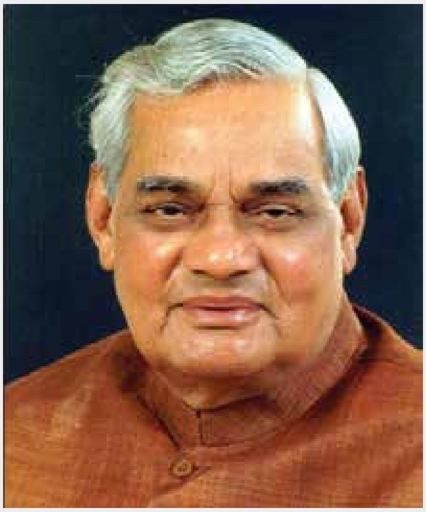

भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत के राजनीतिक इतिहास में एक शिखर पुरुष हैं। वे एक कुशल राजनेता, प्रशासक, कवि व पत्रकार थे। उन्होंने राजनीति को दलगत और स्वार्थ की वैचारिकता से अलग हटकर अपनाया और उसको जिया भी। राजनीतिक जीवन के उतार-चढ़ाव में उन्होंने अपने को सदैव संयमित रखा। राजनीति में धुर विरोधी भी उनकी विचारधारा और कार्यशैली के कायल थे। उन्होंने पोखरण जैसा आणविक परीक्षण कर विश्व में भारत की शक्ति का अहसास कराया।

अटलजी ने 21वीं सदी के मजबूत, समृद्ध और समावेशी भारत की आधारशिला रखी। विभिन्न क्षेत्रों में उनकी दूरगामी नीतियों ने भारत के प्रत्येक नागरिक के जीवन को स्पर्श किया। अटलजी की जीवटता और संघर्ष के कारण ही भारतीय जनता पार्टी का उत्तरोत्तर विकास हुआ। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संदेश को प्रसारित करने के लिए देशभर की यात्रा की।

अटलजी को कविताओं से बड़ा प्रेम था। कविताओं को लेकर उन्होंने कहा था कि मेरी कविता जंग का एलान है, पराजय की प्रस्तावना नहीं। वह हारे हुए सिपाही का नैराश्य-निनाद नहीं, जूझते योद्धा का जय संकल्प है। वह निराशा का स्वर नहीं, आत्मविश्वास का जयघोष है। उनकी कविताओं का संकलन 'मेरी इक्यावन कविताएं' खूब चर्चित रहा जिसमें 'हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा'...खास चर्चा में रही।

जीवन परिचय

श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर, 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित शिंदे की छावनी में हुआ था। अटलजी के पिता का नाम श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी और मां का नाम श्रीमती कृष्णा वाजपेयी था। अटलजी भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे। वे 1968 से 1973 तक भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। श्री वाजपेयी 10 बार लोक सभा के सांसद रहे। वहीं, वे दो बार 1962 और 1986 में राज्यसभा के सांसद भी रहे।

सन् 1957 से 1977 तक वे लगातार बीस वर्षों तक जनसंघ के संसदीय दल के नेता रहे। उन्होंने आपातकाल के खिलाफ संघर्ष किया। आपातकाल के बाद देश की जनता द्वारा चुनी गयी मोरारजी देसाई की सरकार में वे विदेश मंत्री बने। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में उन्होंने हिंदी में भाषण दिया और वे इसे अपने जीवन का अब तक का सबसे सुखद क्षण बताते थे।

सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए विचारधारा की राजनीति करने वाले श्री वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद पहले अध्यक्ष बने। उन्होंने तीन बार 1996, 1998-99 और 1999-2004 में प्रधानमंत्री के रूप में देश का प्रतिनिधित्व किया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 16 अगस्त, 2018 को श्री वाजपेयी का देहावसान हो गया।

संक्षिप्त परिचय

- 25 दिसंबर, 1924 को ग्वालियर में जन्म
- 1957 में पहली बार लोकसभा पहुंचे
- भारत और पाकिस्तान के बीच कटु संबंधों को सुधारने का प्रयास किया; 1999 में लाहौर बस यात्रा की
- 1996 में पहली बार, 1998 में दूसरी बार, 1999 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने
- 1998 में पोखरण परीक्षण करके दृढ़ नेतृत्व का परिचय दिया और विश्व को भारत की परमाणु क्षमता का अहसास कराया
- भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित
- 16 अगस्त, 2018 को देहांत

राष्ट्र निर्माता अटलजी

देश की प्रगति के लिए अटलजी ने 'स्वर्णिम चतुर्भुज' योजना का आरम्भ किया। इसके अंतर्गत वह देश के महत्त्वपूर्ण शहरों को लम्बी-चौड़ी सड़कों के माध्यम से जोड़ना चाहते थे। इसका अधिकांश कार्य अटलजी के कार्यकाल में पूर्ण हुआ। इससे जहां आम व्यक्ति की यात्रा सुविधाजनक हुई, वहीं व्यापारिक और क़ारोबारी गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिला। साथ ही, अटलजी ने पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध सुधारने की दिशा में सदैव पहल की।

अटलजी ने विज्ञान और तकनीक की प्रगति के साथ देश का भविष्य जोड़ा। उन्होंने परमाणु शक्ति को देश के लिए आवश्यक बताकर 11 मई, 1998 को पोखरन में पांच परमाणु परीक्षण किए। परमाणु परीक्षण के कारण अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन अटलजी ने प्रतिबंधों की परवाह न करते हुए भारत को स्वावलम्बी राष्ट्र बनाने की दिशा में कार्य किया। ■

बसवराज बोम्मई बने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री

गत 28 जुलाई को भाजपा नेता श्री बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत ने बेंगलुरु स्थित राज भवन में उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री श्री एस. आर. बोम्मई के बेटे श्री बोम्मई पिछली मंत्रिपरिषद् में गृह मामलों, कानून, संसदीय मामलों और विधायी मामलों के मंत्री थे।

61 वर्षीय श्री बोम्मई हावेरी जिले में शिगगांव से तीन बार के विधायक हैं तथा दो बार वह पार्षद रहे हैं। उनके शपथ ग्रहण समारोह में श्री बी.एस. येदियुरप्पा, केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और श्री जी. किशन रेड्डी, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं कर्नाटक के प्रभारी श्री अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष श्री नलिन कुमार कतील और राष्ट्रीय महामंत्री श्री सी. टी. रवि तथा कई अन्य नेता मौजूद रहे। श्री प्रधान और रेड्डी को विधायक दल की बैठक के लिए भाजपा के संसदीय बोर्ड ने केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया था।

श्री बोम्मई ने एक प्रभावी, ईमानदार और जनता के लिए काम करने वाली सरकार का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि वह सभी को साथ लेकर चलेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार एक टीम के तौर पर काम करेगी। हमारी सरकार कोविड तथा अन्य स्वास्थ्य मुद्दों के साथ ही बाढ़ से प्रभावित लोगों के बचाव के लिए आएगी। हमारे सभी फैसले यह ध्यान में रखते हुए लिए जाएंगे कि समाज के अंतिम व्यक्ति- गरीब, किसानों, पिछड़े और शोषित लोगों को उसका लाभ मिले तथा क्षेत्रीय असंतुलन से भी मुक्ति मिले।

करीब एक सप्ताह बाद श्री बसवराज बोम्मई ने चार अगस्त को अपने मंत्रिपरिषद् का विस्तार किया, जिसमें 29 मंत्रियों को शामिल किया गया। राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत ने राजभवन में नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सर्वश्री शामिल गोविंद कारजोल (मुधोल), केएस ईश्वरप्पा (शिमोगा), आर. अशोक (पद्मनाभनगर), सी. एन. अश्वथ नारायण (मल्लेश्वरम), बी. श्रीरामुलु (मोल्कालमुरु), उमेश कट्टी (हुक्केरी), एस. टी. सोमशेखर (यशंवतपुर), के. सुधाकर (चिक्काबल्लापुरा), बी. सी. पाटिल (हीराकेरुरु), जे. सी. मधुस्वामी (चिक्कनयाकनाहल्ली), प्रभु चौहान (औरद), वी. सोमन्ना (गोविंदराज नगर), एस. अंगारा (सुल्लिया), आनंद सिंह (विजयनगरा), सी. सी. पाटिल (नारगुंड), एम. टी. बी. नागराज (विधान पार्षद), कोटा श्रीनिवास पुजारी (विधान पार्षद), वी. सुनील कुमार (करकला), अरगा जनेंद्र (तीर्थहल्ली), मुनिरत्ना (आर. आर. नगर), हलप्पा अचार (येलबुर्गा), शंकर पाटिल मुनेनकोप (नवलगुंडा) और बी. सी. नागेश (टिपतुर) ने भी मंत्री पद की शपथ ली। ■

'यह देश के वीर जवानों के शौर्य, त्याग और बलिदान का दिवस है'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 26 जुलाई, 2021 को पार्टी के नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय कार्यालय में भारतीय सेना के साहस, शौर्य, पराक्रम व राष्ट्र के प्रति समर्पण के प्रतीक कारगिल विजय दिवस के अवसर पर देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और इस अवसर उपस्थित गणमान्य अतिथियों को संबोधित किया। उन्होंने इस अवसर पर देश की रक्षा में शहीद हुए वीर जवानों की धर्मपत्नियों और देश के रिटायर्ड वीर जवानों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में कई सेना के अधिकारी (रिटायर्ड), वीर चक्र और गैलेंट्री अवार्ड विजेता जवान (रिटायर्ड) एवं उनके परिजन उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन मेजर जनरल (रिटायर्ड) श्री एम. श्रीवास्तव ने किया। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं सांसद श्री अरुण सिंह भी उपस्थित थे।

श्री नड्डा ने कहा कि आज का दिन हम सबके लिए गर्व का विषय है। यह देश के वीर जवानों के शौर्य, त्याग और बलिदान का दिवस है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश की सीमा सुरक्षा को मजबूत किया है और इन्फ्रॉस्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफी काम हुआ है। मोदी सरकार में अब तक हजारों मीटर के कई ऑल वेदर डबल लेन ब्रिज बन चुके हैं। पिछले छः वर्षों में बॉर्डर पर लगभग 4,764 किमी ऑल वेदर रोड बन चुका है। आज हम सेना के आधुनिकीकरण की दिशा में काफी आगे बढ़े हैं। इस क्षेत्र में एफडीआई 74% कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद भाजपा का पर्याय है (Nationalism is synonyms to Bharatiya Janata Party.)। ■

जन आशीर्वाद यात्रा
जनता व सरकार के बीच अद्भुत पहल

सुनील देवधर
राष्ट्रीय मंत्री, भाजपा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले महीने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। सरकार में 36 नए मंत्रियों को सम्मिलित किया गया और 2014 से केंद्र में सरकार आने के बाद यह सबसे बड़ा कैबिनेट विस्तार भी बना। अब नई कैबिनेट में 77 मंत्री हो गए हैं, जो पहले संख्या 52 थी। महिला प्रतिनिधियों की भी इतनी बड़ी संख्या इससे पहले कभी कैबिनेट में नहीं दिखाई दी, जो अब 11 है। मंत्रिमंडल की औसत आयु 50 है। इसके अलावा क्षेत्रीय संतुलन का उत्तम उदाहरण प्रधानमंत्रीजी ने स्थापित किया। नए मंत्रियों के नामों की घोषणा के बाद यह स्पष्ट तरीके से दिखाई दिया कि इस पर गहन विचार किया गया है। अखबारों में इस मंत्रिमंडल की सकारात्मक चर्चा और सराहना हुई और लोगों ने भी इसका स्वागत किया। प्रधानमंत्रीजी ने क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखा, सामाजिक समरसता के भाव को प्राथमिकता पर रखा, पढ़े-लिखे व क्षमता रखने वालों को मंत्रिमंडल में जगह दी। इसे हर स्तर के लोगों द्वारा सराहा गया, फिर चाहे वो मीडिया जगत हो, राजनीतिशास्त्र के पुरोधा या विश्लेषक या एक आम इंसान हो।

प्रधानमंत्रीजी ने संसद में अपने मंत्रिमंडल विस्तार और नए सदस्यों को सम्मिलित किए जाने को लेकर स्वागत की कोशिश की, लेकिन विपक्ष ने ऐसा नहीं होने दिया। अब उन्होंने नए मंत्रियों को एक अनोखे तरीके से जनता के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है कि नवनियुक्त मंत्री जनता तक सीधे रूप से पहुंचें और सरकार के प्रतिनिधियों के रूप में उनसे मिलें। इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 'जन आशीर्वाद यात्रा' के नाम से एक विशेष योजना बनाई गई है। मंत्रियों को स्वतंत्रता दिवस तक दिल्ली में रहने का आग्रह किया गया है। इसलिए 16 अगस्त से यात्रा की योजना बनाई गई है। न्यूनतम 3 से 5 दिनों की अवधि के लिए मंत्री अपने राज्य में यात्रा शुरू करेंगे और पूर्व नियोजित मार्ग से गुजरेंगे। कई गतिविधियां, बैठकों, कार्यक्रमों की योजना बनाई जा रही है। यात्रा मंत्रियों के गृह नगर में समाप्त होगी।

> आजादी के बाद के भारत के इतिहास में इस तरह की गतिविधि पहली बार होने जा रही है, जब मंत्री सड़क पर उतरेंगे और इतनी लंबी यात्रा को करते दिखेंगे। मंत्रियों और आम लोगों की ये बैठकें जनता और सरकार के बीच एक अद्भुत संचार विकसित करने में एक लम्बी यात्रा तय करेंगी

यात्रा की अवधारणा बहुत स्पष्ट है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मंत्री अपनी यात्रा के दौरान समाज के विभिन्न वर्गों से मिलेंगे। वे विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में आम जनता को अवगत कराएंगे। वे योजनाओं के लाभार्थियों से मिलेंगे, उनसे सरकार के प्रति उनकी धारणा, उनके अनुभव आदि के बारे में सुनेंगे। नए मंत्री पूर्व सैनिकों, कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टरों, छात्रों, किसानों, महिलाओं और अन्य सामाजिक समूहों से भी मिलेंगे। वे उन्हें सरकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे। उन्हें जानकारी देंगे कि भाजपा सरकार बनने के बाद किस तरह अनेक विकास कार्यक्रम संभव हो पाए। इस यात्रा की योजना बहुत ही बारीकी से बनाई जा रही है। सूक्ष्म स्तर की योजना में जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की भागीदारी को महत्व दिया गया है। इन कार्यकर्ताओं को न केवल स्वयं सिद्ध करने का मौका मिलेगा, बल्कि बड़े आयोजन की योजना बनाने और उसे धरातल पर उतारने का भी प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा। उन्हें केंद्रीय मंत्री से मिलने का भी अवसर मिलेगा। इतना ही नहीं, जो बैनर आदि लगाए जाएंगे, उन पर भी अलग-अलग संदेश लिखे होंगे।

आजादी के बाद के भारत के इतिहास में इस तरह की गतिविधि पहली बार होने जा रही है, जब मंत्री सड़कों पर उतरेंगे और इतनी लंबी यात्रा को करते दिखेंगे। मंत्रियों और आम लोगों की ये बैठकें जनता और सरकार के बीच एक अद्भुत संचार विकसित करने में एक लम्बी यात्रा तय करेंगी। इस यात्रा के लिए अलग-अलग तरह की छोटी से छोटी गतिविधियों की पहचान की गई है, जिसका नेतृत्व पार्टी का कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता करेगा। इन गतिविधियों में मंदिरों के दर्शन, मूर्तियों पर माल्यार्पण, कोविड-19 केंद्रों का दौरा, टीकाकरण केंद्रों का दौरा, राशन की दुकानों का दौरा आदि सम्मिलित हैं। इसके अलावा बैंक-ऑफिस के काम, जैसे- प्रचार सामग्री का प्रबंधन, सुरक्षा, स्थानीय पुलिस से सामंजस्य, यात्रा की अनुमति प्राप्त करना भी सम्मिलित रहेगा, जिसे पार्टी कार्यकर्ता तय करेगा। इसके अतिरिक्त कार्यकर्ता ही संबंधित प्राधिकारों का गठन करेगा। इन गतिविधियों में पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का सामूहिक प्रयास भी सम्मिलित है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा ने एक-एक यात्रा का अवलोकन किया है और यात्रा के हर एक पहलू पर दृष्टि रखी। राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण चुघ यात्रा पर निगरानी बनाये हुए हैं। वह जन आशीर्वाद यात्रा के राष्ट्रीय प्रभारी भी हैं। पूरी यात्रा

उनकी देखरेख में की जायेगी, पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व यात्राओं पर दृष्टि रखेगा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री एम चुबा ओ, मैं और मेरे साथी चार राष्ट्रीय मंत्री–पंकजा मुंडेजी, अरविंद मेननजी, विनोद सोनकरजी और वाई सत्या कुमारजी के मध्य राज्यों का दायित्व दिया गया है।

इस यात्रा के दौरान बड़ी-छोटी कई सभाएं होंगी। मंत्री स्थानीय मुद्दों पर बात करेंगे, जनता को सीधे तौर पर संबोधित करेंगे और साथ ही संदेश देंगे कि सरकार उनके कल्याण के लिए काम कर रही है और आसानी से उपलब्ध है। यह सरकार और मंत्रियों की सकारात्मक छवि बनाने में भी प्रभावी रहेगा जिससे जनता को अनुभूति कराई जाएगी कि यह सरकार वास्तव में उनका ध्यान रखती है और समस्त जनप्रतिनिधि जमीन से जुड़े कार्यकर्ता से यात्रा करते हुए किस तरह मंत्री पद तक पहुंचे हैं। लोकतंत्र की यह परिभाषा कि सरकार जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए होती है, वास्तव में धरातल पर सिद्ध होती नजर आएगी।

प्रत्येक यात्रा की अधिकतम दूरी 500 किलोमीटर रहेगी। इस यात्रा का एक पूर्व नियोजित मार्ग होगा और प्रत्येक दिन हर मंत्री अधिकतम 100-120 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान करेंगे और मंत्रियों के साथ छोटे समूहों की बैठक की व्यवस्था करेंगे। जैसाकि इसके नाम से ही पता चलता है कि मंत्री जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। प्रत्येक यात्रा एक विशाल आयोजन की तरह होगी, जिसे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, लोकप्रिय यू-ट्यूब चैनल, स्थानीय केबल नेटवर्क आदि के जरिए प्रसारित-प्रकाशित किया जाएगा। इन यात्राओं की योजना महामारी काल में सकारात्मकता का वातावरण बनाने के लिए तैयार की जा रही है। कहने की जरूरत नहीं है कि यात्रा के दौरान सभी कोविड संबंधी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा। यह यात्रा सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को अपने संगठनात्मक कौशल दिखाने का अवसर भी प्रदान करेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, जहां एक कार्यकर्ता को परिश्रम से संगठन और सरकार में बड़े दायित्वों का निर्वाह करने के अवसर प्राप्त होते हैं।

इस लंबी यात्रा की सबसे विशेष पहलू कई अभियानों का एक साथ चलना भी रहेगा यानी कोई केंद्रीय मंत्री सड़क पर जनता से सीधे संवाद करेगा, उनसे आशीर्वाद मांगेगा, स्वच्छ भारत अभियान जैसे कई कार्यक्रमों में भाग लेगा। इस तरह कई पड़ाव से यह यात्रा गुजरेगी। जो रथ इस यात्रा के लिए बनाया जाएगा, वह न तो ज्यादा ऊंचा होगा और उसमे किसी भी रूप से कोई सुविधा और भव्यता नहीं होगी। इसका उद्देश्य सीधे रूप से यही रहेगा कि जनता से सीधा संवाद स्थापित किया जा सके और कोई भी कार्यकर्ता अपने प्रतिनिधि को आसानी से मिल सके, अभिवादन कर सके। यात्रा का मार्ग भी इस तरह बनाया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से, गांवों से, क्षेत्रों से लोग जुड़ सकें। यदि मार्ग में किसी गांव से गुजरेगी, चाहे छोटा हो या बड़ा, तो यात्रा का ठहराव अवश्य होगा ताकि शक्ति केंद्र, मंडल या बूथ समिति के लोग भी अभिवादन कर सकें। यात्रा के लिए एक विशेष तरह का रथ भी तैयार किया जाएगा, जिसे वह राज्य ही बनाएगा, जिससे वह सांसद सम्बन्ध रखता है। ■

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 29.55 करोड़ से ज्यादा उद्यमियों ने 15.52 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लिया

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) और स्टैंडअप इंडिया योजना (एसयूपीआई) उद्यमियों को ऋण देने के लिए वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजनाएं हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत किसानराव कराड ने दो अगस्त को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही।

पीएमएमवाई के तहत सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) द्वारा नए उद्यमों समेत सूक्ष्म अथवा लघु व्यवसाय से जुड़ी इकाइयों को उद्यमशील गतिविधियों के लिए 10 लाख रुपये तक का संस्थागत ऋण प्रदान किया जाता है, जो विनिर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्र और कृषि से जुड़े कार्य जैसे क्षेत्रों में आय पैदा करने वाली गतिविधियां खड़ी करने में मदद करता है। सरकार पीएमएमवाई के तहत मंजूर की जाने वाली राशि के संबंध में एमएलआई के लिए वार्षिक लक्ष्य आवंटित करती है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में एमएलआई के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मंत्री द्वारा बताया गया कि सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) द्वारा मुद्रा पोर्टल पर 31 मार्च, 2021 तक अपलोड किए गए डाटा के मुताबिक अप्रैल, 2015 में इस योजना के शुरू होने के बाद से अब तक देशभर में पीएमएमवाई के तहत 15.52 लाख करोड़ रुपये के 29.55 करोड़ से ज्यादा कर्ज मंजूर किए गए हैं। इनमें से 5.20 लाख करोड़ रुपये के 6.80 करोड़ से ज्यादा कर्ज नई उद्यमियों/खातों को दिए गए हैं।

एक अन्य फ्लैगशिप योजना स्टैंडअप इंडिया (एसयूपीआई) का ब्यौरा देते हुए मंत्री ने कहा कि यह विनिर्माण व्यापार या सेवा क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यम की स्थापना और कृषि से संबद्ध गतिविधियों के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रति बैंक शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्जदार और कम से कम एक महिला कर्जदार को 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करती है।

वित्त राज्यमंत्री द्वारा यह भी बताया गया कि सरकार पीएमएमवाई और एसयूपीआई के क्रियान्वयन के संबंध में समय-समय पर मिलने वाली शिकायतों को लेकर भी कदम उठाती है। इनमें कर्ज के आवेदनों को ठुकराने या निधियों को जारी न करने की शिकायतें शामिल हैं। इन शिकायतों का संबंधित बैंक के साथ समन्वय बनाकर निराकरण किया जाता है। ■

वर्तमान में हम भारत के इतिहास में महिला सशक्तिकरण का स्वर्ण युग देख रहे हैं: वानथी श्रीनिवासन

भारतीय जनता पार्टी, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और कोयंबटूर दक्षिण से तमिलनाडु विधानसभा की सदस्य श्रीमती वानथी श्रीनिवासन पार्टी की ऊर्जावान महिला नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक बहुत ही विनम्र कृषि परिवार से आनेवाली श्रीमती श्रीनिवासन ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् में अनेक दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। उन्होंने महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभालने से पहले भाजपा, तमिलनाडु प्रदेश मंत्री, महामंत्री और उपाध्यक्ष के रूप में कई जिम्मेदारियां निभाईं। अपने संगठनात्मक कौशल के लिए जानी जानेवाली श्रीमती श्रीनिवासन ने तमिलनाडु में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की और इस चुनाव में उन्होंने एक नामी फिल्म अभिनेता को हराया था।

श्रीमती वानथी श्रीनिवासन से उनके नई दिल्ली स्थित निवास पर कमल संदेश के सह संपादक संजीव कुमार सिन्हा और राम प्रसाद त्रिपाठी ने महिला मोर्चा की सक्रियता एवं मोदी सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे कार्यों को लेकर बातचीत की। प्रस्तुत है प्रमुख अंश:

सबसे पहले हम आपको कोयंबटूर दक्षिण विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बधाई देते हैं।

आपके अभिवादन के लिए धन्यवाद।

'बेटी बचाओ—बेटी पढ़ाओ' से लेकर अधिकतम महिला मंत्रियों को मंत्रिपरिषद् में शामिल करने तक, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्ववाली केंद्र सरकार ने लैंगिक न्याय और महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक कदम उठाए हैं। एक महिला के तौर पर आप इसे कैसे देखती हैं?

जहां तक स्त्रीशक्ति के हित के लिए विभिन्न कदमों का सवाल है, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार देश की बेटियों के दर्द और चुनौतियों को समझती है और उनका समयबद्ध तरीके से समाधान करने के लिए कटिबद्ध है। यह सरकार महिलाओं को उनके अधिकार देकर उन्हें सशक्त बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

इसके अलावा, भाजपा देश की एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है जो पार्टी में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर रही है। पार्टी न केवल महिलाओं को चुनाव लड़ने का मौका दे रही है, बल्कि पंचायत से लेकर संसद तक केंद्रीय मंत्रिपरिषद् सहित सरकार के हर स्तर पर उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर रही है, जिससे सरकार के सर्वोच्च निर्णय लेनेवाले निकाय में महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो सके।

मैं आपसे सहमत हूं कि 'बेटी बचाओ—बेटी पढ़ाओ' से लेकर 'सुकन्या समृद्धि योजना' तक, मातृत्व अवकाश देने से लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम महिलाओं को शामिल करने तक, भाजपा नेतृत्ववाली सरकार ने बड़े पैमाने पर महिलाओं के हित में अनेक योजनाएं प्रारंभ की है। किसी अन्य सरकार ने महिलाओं को शासन में इतना सम्मान और प्रतिनिधित्व नहीं दिया, जितना मोदी सरकार ने दिया है। एक महिला के रूप में मुझे संगठन का हिस्सा होने पर गर्व महसूस होता है और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में वर्तमान में हम भारत के इतिहास में महिला सशक्तिकरण का स्वर्ण युग देख रहे हैं।

किसी देश को सशक्त बनाने के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण बेहद जरूरी है। इस संदर्भ में देखा जाए तो हाल ही में अधिकतम महिलाओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करना कितना महत्वपूर्ण है?

प्रधानमंत्री श्री मोदी शुरू से ही इस बात पर जोर देते रहे हैं कि किसी देश को सशक्त बनाने के लिए महिला सशक्तिकरण बेहद जरूरी है। इसलिए, पिछले सात वर्षों में प्रधानमंत्रीजी ने यह सुनिश्चित किया है कि महिलाओं को पर्याप्त सम्मान एवं भरपूर अवसर मिले।

स्वतंत्रता के बाद के भारत में संभवतः यह पहली बार है जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद् में इतनी बड़ी संख्या में महिला मंत्री शामिल हैं। प्रधानमंत्रीजी ने सात और महिला मंत्रियों को शामिल किया है, जिसके बाद अब महिला मंत्रियों की कुल संख्या 11 हो गयी है। प्रधानमंत्रीजी का यह कदम दर्शाता है कि भारत 'महिलाओं के विकास' से आगे बढ़कर 'महिला नेतृत्ववाले विकास' की ओर जा रहा है। ये मंत्री देश भर से हैं और समाज के सभी वर्गों और तबकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इन महिला मंत्रियों के नेतृत्व में महिला केंद्रित मुद्दों और नीतियों को प्राथमिकता मिलनी तय है जैसा पहले कभी नहीं हुआ।

मोदी सरकार ने हमारे देश की महिला आबादी की बेहतरी के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है। भाजपा महिला मोर्चा इस संदेश को जमीनी स्तर पर ले जाने और कल्याणकारी योजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने को लेकर क्या योजना बना रहा है?

'जन-धन योजना' का उदाहरण हमारे सामने हैं, महिलाएं इस योजना की प्रमुख लाभार्थी हैं और मोदीजी जानते हैं कि यदि एक महिला अपना एक नया पैसा भी खर्च करती है, तो वह उसके परिवार के कल्याण के लिए होता है। इसलिए प्रधानमंत्रीजी ने महिलाओं के खाते में पैसा जमा कराया। 'स्वच्छ भारत' में भी सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं को ही मिला है। इसी तरह 'उज्ज्वला' है, जिसमें भी महिलाएं ही प्रमुख लाभार्थी हैं, और यह उन्हें पारंपरिक तरीके से ईंधन के प्रयोग से मुक्ति प्रदान करता है जो कई बीमारियों का कारण बनता था। 'आवास योजना' में भी महिलाएं प्रमुख लाभार्थी हैं और उनके नाम संपत्ति कर महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्रीजी ने बेटियों को हर क्षेत्र में अपनी सही जगह हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया है वह वास्तव में अभूतपूर्व और सराहनीय है। भाजपा महिला मोर्चा इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए महिलाओं में जागरूकता पैदा कर रही है और आनेवाले दिनों में हम प्रत्येक लाभार्थी के घर तक जाने का प्रयास करेंगे।

- **मोदी सरकार महिलाओं को उनके अधिकार देकर उन्हें सशक्त बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध है**
- **भारतीय जनता पार्टी न केवल महिलाओं को चुनाव लड़ने का मौका दे रही है, बल्कि पंचायत से लेकर संसद तक केंद्रीय मंत्रिपरिषद् सहित सरकार के हर स्तर पर उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर रही है**
- **भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित अमृत महोत्सव के निमित्त हम 75 महिला स्वतंत्रता सेनानियों के जन्मस्थान एवं स्मारकों पर एक कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रहे हैं**

महिलाओं के लिए जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की नई अधिवास (डोमिसाइल) नीति कितनी महत्वपूर्ण है?

पुराना स्थायी निवासी नियम जम्मू और कश्मीर की महिलाओं के साथ भेदभाव करता था क्योंकि यह नियम उनको किसी गैर-स्थायी निवासी के साथ शादी करने के बाद राज्य से प्राप्त अधिकार से वंचित कर देता था। लेकिन नई डोमिसाइल नीति ने राज्य की महिलाओं को विवाह की स्वतंत्रता देकर और उनके डोमिसाइल को बनाए रखने के साथ-साथ समाज में समान भागीदारी का अधिकार प्रदान कर न्याय प्रदान किया है। अब उनके जीवन-साथी भी डोमिसाइल नीति के तहत लाभ पाने के हकदार हैं।

जब एक लड़की केवल राज्य की सीमाओं के बाहर जीवन-साथी चुनने के लिए अपनी नागरिकता और संपत्ति खो देती है, तो ऐसी भेदभावपूर्ण प्रथा को रोकने के लिए भाजपा के अलावा किसी अन्य राजनीतिक दल ने इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं दिखाई। भाजपा महिला मोर्चा ने इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। जम्मू-कश्मीर की कई महिलाओं को डोमिसाइल अधिकारों से लाभ होगा, जिनसे वे दशकों से वंचित थीं।

भाजपा ने कोविड-19 महामारी के दौरान 'सेवा ही संगठन' की शुरुआत की। महिला मोर्चा ने इस अभियान में कैसे अपना योगदान दिया?

कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा शुरू किए गए 'सेवा ही संगठन' अभियान के तहत पार्टी की लाखों महिला कार्यकर्ता अपने घरों से जरूरतमंदों की सेवा के लिए भोजन, आवश्यक सामग्री और रक्तदान के लिए निकलीं। 22 राज्यों से उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार 55,58,294 मास्क, 46,86,686 भोजन के पैकेट, 47,88,522 राशन के पैकेट, 3,76,498 सेनेटरी पैड / सैनिटाइज़र वितरित किए गए और 11,645 महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंदों को रक्तदान किया।

आपके कार्यभार संभालने के बाद, भाजपा महिला मोर्चा की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में कुछ बताएं?

महिला मोर्चा ने अधिकांश राज्यों में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठकें पूरी कर ली हैं। अब हमारा ध्यान मंडलस्तरीय समितियां, बूथ समितियां और पन्ना प्रमुखों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने पर है। हम बूथ समितियों में एक तिहाई महिलाओं को शामिल करने के लिए काम कर रहे हैं।

दूसरे, हम महिला केंद्रित मुद्दों के सुचारू समाधान और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पंचायत से संसद तक एक संगठनात्मक नेटवर्क का निर्माण कर रहे हैं।

तीसरा, हम सर्वस्पर्शी कार्य करते हुए प्रत्येक महिला तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हम हर राज्य में महिला प्रतिनिधियों का सम्मान और अभिनंदन करेंगे। हम उनसे जुड़ना चाहते हैं क्योंकि ये महिलाएं प्रधानमंत्री की योजनाओं के प्रचार और प्रसार में महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती हैं।

भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित अमृत महोत्सव के निमित्त हम 75 महिला स्वतंत्रतासेनानियों के जन्मस्थान/स्मारकों पर एक कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। इस अवसर पर हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेनेवाली इन गुमनाम महिला नेताओं पर एक पुस्तक भी प्रकाशित करने की योजना बना रहे हैं। ■

मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल

ई-रुपी से जनता को सीधा लाभ

आम आदमी के जीवन में क्रांति लाने के लिए वित्तीय तकनीकों का उपयोग करना प्रधानमंत्री की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। प्रधानमंत्री फिनटेक समाधानों के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डेटा मैनेजमेंट का उपयोग करके नवाचार लागू करने के लिए स्टार्ट-अप्स को निरंतर प्रोत्साहित कर रहे हैं

गोपाल कृष्ण अग्रवाल
राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ई-रुपी वाउचर लॉन्च किया। यह मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस प्रणाली को लागू करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, 'यह लक्षित, पारदर्शी और रिसाव मुक्त वितरण में मदद करेगा। ई-रुपी इस बात का प्रतीक है कि लोगों के जीवन को प्रौद्योगिकी से जोड़कर भारत कैसे प्रगति कर रहा है।'

2014 में जब श्री नरेन्द्र मोदी शासन में आए तो सरकारी वितरण तंत्र में बड़े पैमाने पर रिसाव हुआ करता था। सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाएं लाभार्थियों तक कुशलतापूर्वक नहीं पहुंच रही थीं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य, मोदीजी के लिए सामाजिक कल्याण लाभ के लिए वितरण तंत्र को सुव्यवस्थित करना था, जिसमें भ्रष्टाचार और अन्य रिसावों के लिए स्थान नहीं रहे। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) की उन्होंने ऐतिहासिक पहल की थी। जन-धन खाते खोलना, इसे आधार कार्ड से जोड़ना और ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के लिए डिजिटल तकनीकों के उपयोग के द्वारा वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को लागू किया गया, जिसे 'जैम ट्रिनिटी' कहा जाता है। इसे विश्व बैंक द्वारा दुनिया भर में सबसे प्रभावी वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों में से एक के रूप में सराहा गया है। ऑनलाइन भुगतान तकनीक जैसे भीम और #99 ऐप आदि के लिए अधिक से अधिक एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) विकसित किए गए और उनके माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में धनराशि स्थानांतरित की गई।

आम आदमी के जीवन में क्रांति लाने के लिए वित्तीय तकनीकों का उपयोग करना प्रधानमंत्री की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। प्रधानमंत्री फिनटेक समाधानों के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डेटा मैनेजमेंट का उपयोग करके नवाचार लागू करने के लिए स्टार्ट-अप्स को निरंतर प्रोत्साहित कर रहे हैं। टैक्स रियायतों के माध्यम से स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र बनाना और फिर उसके लिए निवेश योग्य धन उपलब्ध कराने के साथ, सरकार का एक स्पष्ट रोडमैप है। अटल टिंकरिंग लैब और अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से अकादमिक और उद्योगों को जोड़ने के लिए भी योजनाएं बनायी गयी हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा नवाचार प्रोत्साहन के लिए हैकाथॉन का आयोजन और फिर उसके उत्पादन के लिए पूर्ण सहयोग करना और समूची पेटेंट व्यवस्था को सुदृढ़ करना सरकार की नई पहल है। फिनटेक नवाचारों और समाधानों ने भारत में वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में अत्यधिक क्रांति ला दी है। वर्ष 2021 में 32 यूनिकॉर्न (एक बिलियन डॉलर मूल्य की स्टार्ट-अप कंपनी) में से नौ वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियां हैं।

इस डिजिटल परिवर्तन ने अमीर और गरीब, शहरी और ग्रामीण आबादी के बीच तकनीकी दूरी को कम करने में मदद की है। पंचायत स्तर पर इंटरनेट कनेक्टिविटी का एकीकृत तंत्र बनाया गया जा रहा है। डिजिटल-इंडिया प्लेटफॉर्म के तहत भी कंप्यूटर सेवा केंद्र (सीएससी) स्थापित कर, लोगों के जीवन को सुगमता प्रदान की जा रही है

इस डिजिटल परिवर्तन ने अमीर और गरीब, शहरी और ग्रामीण आबादी के बीच तकनीकी दूरी को कम करने में मदद की है। पंचायत स्तर पर इंटरनेट कनेक्टिविटी का एकीकृत तंत्र बनाया गया जा रहा है। डिजिटल-इंडिया प्लेटफॉर्म के तहत भी कंप्यूटर सेवा केंद्र (सीएससी) स्थापित कर, लोगों के जीवन को सुगमता प्रदान की जा रही है। तकनीक का इस्तेमाल करते हुए मोदी सरकार 'न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन' के अपने वादे को पूरा कर रही है। प्रौद्योगिकी समाधानों ने सरकारी निर्णय और उसके कार्यान्वयन में मानवीय हस्तक्षेप और व्यक्तिपरकता को काफी हद तक कम कर दिया, जिससे सभी को अपने दैनिक जीवन-यापन में सुविधा मिली है। सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए ऑनलाइन समाधान मानवीय हस्तक्षेप को कम करता है और इसमें भ्रष्टाचार की संभावनाएं भी कम होती हैं।

डिजिटल-इंडिया पहल जैसे जीएसटी का कार्यान्वयन, वर्चुअल ई-मूल्यांकन, सरकारी ई-मार्केट (जीईएम) प्लेटफॉर्म, डिजिटल लॉकर, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी), ऑनलाइन भुगतान; भीम

ऐप और #99, ई-मंडियां, 59 मिनट में पीएसबी लोन, स्टार्ट-अप इकोसिस्टम, आरोग्य सेतु और कोविन ऐप, टोल प्लाजा पर फास्ट टैग सुविधा और अब ई-रुपी वाउचर ने आम लोगों के जीवन को बदल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी, सरकारी योजनाओं को कुशलतापूर्वक लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में सफल रहे हैं, चाहे वह लक्षित व्यक्तियों तक सामाजिक लाभ पहुंचाना हो, या व्यवसाय करने में आसानी (ईओडीबी) या फिर लाभ वितरण और शासन के लिए भ्रष्टाचार मुक्त तंत्र का निर्माण करना हो। अकेले जुलाई महीने में, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने रिकॉर्ड 324 करोड़ लेनदेन संसाधित किए हैं। अगर राशि की बात करे तो इस प्लेटफॉर्म से 6.06 लाख करोड़ रुपये के लेनदेन को संसाधित किया जा चुका है।

हमारी सरकार 300 सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लक्षित लाभार्थियों को 17.5 लाख करोड़ रुपये की धनराशि हस्तांतरित करने में सफल रही है और इस राशि को गलत हाथों में जाने से रोककर 1.75 लाख करोड़ रुपये की बचत करने में भी सफल रही है। इस साल सरकार ने न्यूनतम मूल्य पर खाद्यान्न खरीद कर किसानों के खाते में 86 हजार करोड़ रुपये ट्रांसफर किए हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत भी बड़ी राशि सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर की है। ई-रुपी वाउचर की यह नई पहल लक्षित व्यक्ति तक फंड ट्रांसफर करने के लिए एक अभिनव साधन बनकर उभरेगी। जब सरकार ई-रुपी वाउचर जारी करती है, तो वह सुनिश्चित करती है कि फंड का उपयोग केवल निश्चित उद्देश्य के लिए ही किया जा सकता है। यह व्यक्ति-विशिष्ट भुगतान प्रणाली प्री-पेड उपहार-वाउचर के रूप में कार्य करती है, निर्धारित सेवा केंद्रों पर भुनाया जा सकता है। यह योजना सेवाओं के प्रायोजकों, लाभार्थियों और सेवा प्रदाताओं को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ ले आयेगी। एक बार जब यह वाउचर किसी निजी संगठनों या व्यक्ति द्वारा जारी किया जाएगा, तो उसे इस बात का भरोसा होगा कि इस निधि का उपयोग उनके निर्देशानुसार ही होगा। इसका उपयोग कॉरपोरेट्स द्वारा (सीएसआर) गतिविधियों के लिए, धर्मार्थ संस्थानों द्वारा दान और थर्ड पार्टी भुगतान के लिए भी किया जा सकता है।

सरकार 'पुश मॉडल' पर काम कर रही है, जहां योजनाओं की घोषणा की जाती है, लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और सरकारी अधिकारियों को उनके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार बनाया जाता है, न कि पुल मॉडल पर जहां नागरिकों को लाभ लेने के लिए सरकारी विभागों के पीछे भागना पड़ता है। 115 आकांक्षी जिलों की पहचान करना और उनके अन्तर्गत जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित करना की लाभार्थियों को सरकारी योजनाओ का लाभ प्राप्त हो, यह एकीकृत समाधान इसका एक उदाहरण है। श्री नरेन्द्र मोदी का यह प्रयास रहा है कि किसी भी समस्या की पहचान की जाए, इसके समाधान के लिए एक तकनीकी तंत्र तैयार किया जाए, सभी हितधारकों को उससे जोड़ा जाए और इस तंत्र के कुशल कार्यान्वयन और मूल्यांकन के लिए परफॉर्मेंस मैट्रिक्स स्थापित किया जाए ताकी जवाबदेही सुनिश्चित हो। ■

पूर्वी बेड़े के जहाज़ अभियानगत विदेशी तैनाती पर

भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति के अनुरूप और मित्र देशों के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का एक कार्यबल अगस्त, 2021 की शुरुआत से दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण चीन सागर और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में दो महीने से अधिक के लिए विदेशी तैनाती पर जाना निर्धारित है।

भारतीय नौसेना के जहाजों की तैनाती के पीछे सामुद्रिक क्षेत्र में बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करना और भारत और भारत प्रशांत क्षेत्र के देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में मित्र देशों के साथ अभियानगत पहुंच, शांतिपूर्ण उपस्थिति और एकजुटता को रेखांकित करना है।

भारतीय नौसेना कार्य समूह में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर रणविजय, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट शिवालिक, एंटी-सबमरीन कार्वेट कदमत और गाइडेड मिसाइल कार्वेट कोरा शामिल हैं। बाद के तीन जहाज स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए हैं और वे हथियारों और सेंसर की एक बहुमुखी एरे से लैस हैं और रक्षा शिपयार्ड द्वारा भारत में निर्मित हैं।

इंडो पैसिफिक में तैनाती के दौरान जहाजों को वियतनामी पीपुल्स नेवी, रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस नेवी, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी, इंडोनेशियन नेवी और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ द्विपक्षीय अभ्यास में भाग लेना है। इसके अलावा, वे जापान मेरिटाइम सेल्फ डिफेंस फ़ोर्स, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के साथ बहुपक्षीय अभ्यास मालाबार-21 में भी भाग लेंगे।

प्रधानमंत्री की 'सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फ़ॉर ऑल इन द रीजन-सागर' पहल को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना मित्र देशों और भारतीय एवं प्रशांत महासागर क्षेत्र में नियमित तैनाती करती है। इसके अलावा इस तरह के ताल्लुक 'दोस्ती के पुल' का निर्माण करते हैं और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करते हैं। यह समुद्री पहल आम समुद्री हितों और समुद्र में नौवहन की स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता के आधार पर भारतीय नौसेना और मित्र देशों के बीच तालमेल और समन्वय को बढ़ाती है। नियमित पोर्ट कॉल के अलावा टास्क ग्रुप सैन्य संबंध बनाने और समुद्री अभियानों के संचालन में अंतर-संचालनीयता विकसित करने के लिए मैत्रीपूर्ण नौसेनाओं के साथ मिलकर काम करेगा। ■

उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज एक विशाल संकुल बनाकर आगे बढ़ेगाः अमित शाह

लखनऊ में बनने वाले उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज पर क़रीब 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे

गत एक अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास किया। उन्होंने एक पौधा भी लगाया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप-मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य, उप-मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज एक विशाल संकुल बनाकर आगे बढ़ेगा। आज इसका बीजारोपण हुआ है, मगर जब यह वटवृक्ष होगा तब अनेक बच्चे यहां से अपना कैरियर बनाएंगे। अनेक बच्चे यहां अनुसंधान में हिस्सा लेकर न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश की क़ानून और व्यवस्था की रीढ़ बनने का काम करेंगे।

उन्होंने कहा कि लखनऊ में बनने वाले उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज पर क़रीब 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। साथ ही भारत सरकार ने यहां एक डीएनए केन्द्र बनाने के लिए 15 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है जिससे यहां देश का सबसे आधुनिक डीएनए केन्द्र बनाया जाएगा।

श्री शाह ने कहा कि विकास की 44 योजनाओं में देश में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। उन्होंने कहा कि योजनाएं बनाना बहुत सरल होता है लेकिन योजनाओं को भूमि पर उतारना, उन्हें लाभार्थी तक पहुंचाना, इनसे बिचौलियों को समाप्त कर देना और लाभार्थी को बिना किसी कष्ट व रिश्वत के योजनाओं का लाभ मिले ऐसा तंत्र बनाना बहुत ही कठिन है। योगीजी और उनकी टीम 44 योजनाओं में पूरे देश में सर्वप्रथम स्थान हासिल किया है और यह हम सबके लिए गौरव की बात है।

गृह मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास किया है। चाहे औद्योगिक निवेश की बात हो, योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो, क़ानून व्यवस्था ठीक करना हो, गरीब किसान का ऋण माफ़ करना हो, चाहे गरीब किसान के अनाज का मूल्य बिचौलियों के बिना सीधे उसके बैंक खाते में डालने की बात हो, हर घर में शौचालय बनवाना हो, हर घरविहीन लोगों को घर देना हो, 1.47 करोड़ महिलाओं को गैस का सिलेंडर देना, बिजली पहुंचाने या फिर भ्रष्टाचार पर नकेल कसना हो हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने योगीजी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया है।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2017 में हमने जो वायदे किए थे उन सबको पूरा कर हम 2024 में राज्य की जनता के सामने जाएंगे।

उत्तर प्रदेश के लोगों ने दंगाविहीन राज्य की कल्पना भी नहीं की थी, युवाओं ने रोज़गार की कल्पना ही नहीं थी, व्यापारियों ने सफलता के साथ अनधिकृत टैक्स दिए बिना व्यापार की कल्पना नहीं की थी और उत्तर प्रदेश में इतने अधिक औद्योगिक निवेश के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे बदलकर राज्य को बहुत आगे बढ़ाया है।

'मां विंध्यवासिनी' कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास

गत एक अगस्त को केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर में 'मां विंध्यवासिनी' कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास किया। श्री शाह ने कहा कि आज 'मां विंध्यवासिनी' कॉरिडोर का शिलान्यास और रोपवे के लोकार्पण होने से अब किसी श्रवण कुमार को अपने बूढ़े माता-पिता को कांवड़ में लाने की आवश्यकता नहीं है, वह रोपवे से उन्हें त्रिकोण परिक्रमा पूरी करा सकता है।

उन्होंने कहा कि मैं पूर्ववर्ती सरकारों से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने इन तीर्थस्थलों का विकास क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें वोट बैंक की राजनीति से डरती थीं, लेकिन उनकी सरकार इससे नहीं डरती। गृह मंत्री ने कहा कि यह आज जो सारे विकास के कार्य हो रहे हैं उससे श्रद्धालुओं को सुविधा मिलने के साथ ही इस क्षेत्र में पर्यटन तथा रोज़गार को बढ़ावा मिलेगा।

श्री शाह ने कहा कि उन्होंने भी आज 'मां विंध्यवासिनी' के दर्शन कर उत्तर प्रदेश के सुख और स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए मन से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि विंध्यवासिनी परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जो रोपवे बना है और जो अन्य विकास कार्य हो रहे हैं उनके लिए योगीजी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ■

स्वदेशी विमानवाहक पोत 'विक्रांत' के समुद्री परीक्षणों की शुरुआत

आत्मनिर्भर भारत व 'मेक इन इंडिया' के तहत तैयार हुए देश के पहले विमानवाहक युद्धपोत 'विक्रांत' का समुद्री परीक्षण 4 अगस्त से शुरू हो गया। यह ट्रायल के लिए समुद्र में उतरा। भारतीय नौसेना के नौसेना डिजाइन निदेशालय (डीएनडी) द्वारा डिजाइन किया गया स्वदेशी विमानवाहक (आईएसी) पोत 'विक्रांत' पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओएस) के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) में बनाया गया है। आईएसी 76 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ 'आत्मनिर्भर भारत' के लिए देश के प्रयास का एक प्रमुख उदाहरण है। यह भारतीय नौसेना और कोचीन शिपयार्ड का स्वदेशी रूप से एक विमानवाहक पोत डिजाइन करने निर्माण करने का पहला प्रयास है।

स्वदेशी विमानवाहक पोत 262 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा और 59 मीटर ऊंचा है, जिसमें सुपरस्ट्रक्चर भी शामिल है। सुपरस्ट्रक्चर में पांच डेक होने समेत पोत में कुल 14 डेक हैं। जहाज में 2,300 से अधिक कम्पार्टमेंट्स हैं, जिन्हें लगभग 1700 लोगों के क्रू के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें महिला अधिकारियों को समायोजित करने के लिए विशेष केबिन भी शामिल हैं। जहाज को मशीनरी संचालन, जहाज नेविगेशन और कठिन हालात में स्वयं को बनाए रखने के दृष्टिकोण से बहुत उच्च स्तर के ऑटोमेशन के साथ डिजाइन किया गया है। 'विक्रांत' की लगभग 28 समुद्री मील की शीर्ष गति और लगभग 7,500 समुद्री मील की एंड्योरेंस के साथ 18 समुद्री मील की परिभ्रमण गति है। जहाज फिक्स्ड विंग और रोटरी एयरक्राफ्ट के वर्गीकरण को समायोजित कर सकता है।

स्वदेशी विमानवाहक पोत 262 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा और 59 मीटर ऊंचा है, जिसमें सुपरस्ट्रक्चर भी शामिल है। सुपरस्ट्रक्चर में पांच डेक होने समेत पोत में कुल 14 डेक हैं। जहाज में 2,300 से अधिक कम्पार्टमेंट्स हैं, जिन्हें लगभग 1700 लोगों के क्रू के लिए डिज़ाइन किया गया है

अधिकांश जहाज के निर्माण की गतिविधियां पूरी हो चुकी हैं और यह परीक्षण के चरण में प्रवेश कर चुका है। जहाज के प्रणोदन और बिजली उत्पादन उपकरण/प्रणालियों की तैयारी का परीक्षण 20 नवंबर को बेसिन परीक्षणों के अंतर्गत बंदरगाह में किया गया था। जहाज के निर्माण की प्रगति की समीक्षा रक्षा मंत्री द्वारा 25 जून, 2021 को जहाज के दौरे के दौरान की गई थी। हालांकि, अपना दिल और आत्मा जहाज की तैयारी के लिए लगाने वाले बड़ी संख्या में कामगारों, ओईएम, इंजीनियरों, ओवरसियरों, निरीक्षकों, डिजाइनरों और जहाज के चालक दल के केंद्रित और समर्पित प्रयासों के साथ कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण समुद्री परीक्षण शुरू होने में देरी हुई।

स्वदेशी विमानवाहक पोत की डिलीवरी के साथ भारत स्वदेशी रूप से डिजाइन और एक विमानवाहक बनाने की क्षमता वाले देशों के चुनिंदा समूह में शामिल हो जाएगा, जो भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया' मुहिम का एक वास्तविक प्रमाण होगा।

एयरक्राफ्ट कैरियर का स्वदेशी निर्माण 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' की दिशा में देश के प्रयास का एक जीवंत उदाहरण है। इससे बड़ी संख्या में सहायक उद्योगों के विकास के अलावा 2000 सीएसएल कर्मियों और सहायक उद्योगों में लगभग 12000 कर्मचारियों के लिए रोजगार के अवसरों के साथ स्वदेशी डिजाइन और निर्माण क्षमताओं में वृद्धि हुई है। उपकरणों की खरीद के मामले में 76 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री, सीएसएल और उनके उप-ठेकेदारों द्वारा काम का फायदा सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था को होने जा रहा है। लगभग 100 एमएसएमई सहित लगभग 550 भारतीय फर्म सीएसएल के साथ पंजीकृत हैं, जो आईएसी के निर्माण के लिए विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रही हैं।

भारतीय नौसेना का जहाज निर्माण कार्यक्रम 44 जहाजों और पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण के क्रम में अपेक्षित 'आर्थिक प्रोत्साहन' प्रदान करने के लिए सही ढंग से तैयार है।

प्रधानमंत्री ने दी बधाई

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 4 अगस्त को स्वदेशी विमान वाहक पोत 'विक्रांत' की पहली समुद्री यात्रा के लिए भारतीय नौसेना और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को बधाई दी। श्री मोदी ने कहा कि यह 'मेक इन इंडिया' का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि भारतीय नौसेना की डिजाइन टीम द्वारा डिज़ाइन किया गया और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित स्वदेशी विमान वाहक 'विक्रांत' ने आज अपनी पहली समुद्री यात्रा की। यह मेक इन इंडिया का एक अद्भुत उदाहरण है। इस ऐतिहासिक मील के पत्थर के लिए भारतीय नौसेना और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को बधाई। ■

ई-रुपी वाउचर से लक्षित, पारदर्शी और लीकेज मुक्त वितरण में सभी को मिलेगी बड़ी मदद: नरेन्द्र मोदी

भारत में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 17.5 लाख करोड़ रुपये सीधे लोगों के खातों में हस्तांतरित किए गए। 300 से ज्यादा योजनाएं डीबीटी का उपयोग कर रही हैं

गत दो अगस्त को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'ई-रुपी' का शुभारंभ किया जो सही अर्थों में व्यक्ति-विशिष्ट और उद्देश्य-विशिष्ट डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन है। 'ई-रुपी' दरअसल डिजिटल पेमेंट के लिए एक नकद रहित (कैशलेस) और संपर्क रहित साधन है।

आयोजन के दौरान संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 'ई-रुपी' वाउचर देश में डिजिटल ट्रांजेक्शन में डीबीटी को और भी अधिक प्रभावकारी बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा एवं डिजिटल गवर्नेंस को एक नया आयाम देगा। इससे लक्षित, पारदर्शी और लीकेज मुक्त वितरण में सभी को बड़ी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ई-रुपी' इस बात का प्रतीक है कि भारत किस तरह से लोगों के जीवन को प्रौद्योगिकी से जोड़कर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इस बात पर भी प्रसन्नता व्यक्त की कि यह भविष्यवादी या अत्याधुनिक सुधार पहल ऐसे समय में की गई है जब देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर 'अमृत महोत्सव' मना रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार के अतिरिक्त अगर कोई संगठन किसी के इलाज, शिक्षा या अन्य किसी काम में सहायता करना चाहता है तो वह नकद की जगह ई-रुपी वाउचर देने में सक्षम होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि उसके धन का उपयोग उस काम के लिए ही किया गया है, जिसके लिए रकम दी गई थी। श्री मोदी ने कहा कि ई-रुपी व्यक्ति के साथ-साथ उद्देश्य विशिष्ट है। ई-रुपी यह सुनिश्चित करेगा कि धन का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जा रहा है जिसके लिए कोई सहायता या कोई लाभ प्रदान किया गया।

श्री मोदी ने बीते वक्त का स्मरण करते हुए कहा कि एक समय ऐसा था जब तकनीक को संपन्न लोगों का क्षेत्र माना जाता था और भारत जैसे गरीब देश में तकनीक का क्या काम, ऐसी सोच थी। उन्होंने इस बात को भी याद किया, जब इस सरकार ने तकनीक को एक मिशन के रूप में लिया था, तब राजनीतिक नेताओं और कुछ खास तरह के विशेषज्ञों ने इस पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा कि आज देश ने उन लोगों की सोच को भी खारिज कर दिया और उन्हें गलत साबित कर दिया है। आज देश की सोच अलग है, यह नई है। आज हम तकनीक को गरीबों की सहायता करने और उनकी प्रगति के लिए एक उपकरण के रूप में देख रहे हैं।

श्री मोदी ने बताया कि तकनीक किस तरह से लेनदेनों में पारदर्शिता और प्रमाणिकता ला रही है व नए अवसर पैदा कर रही है, साथ ही उन्हें गरीबों को उपलब्ध करा रही है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में विशेष उत्पादों तक पहुंच के लिए मोबाइल और आधार को जोड़ने वाली जेएएम प्रणाली की स्थापना के द्वारा वर्षों के दौरान नींव तैयार की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जेएएम के लाभ लोगों को नजर आने में कुछ समय लगा और हमने देखा कि

लॉकडाउन के दौरान जब दूसरे देशों को लोगों तक सहायता पहुंचाने के लिए जूझना पड़ रहा था, वहीं हम जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाने में कामयाब रहे।

डीबीटी का उपयोग कर रही हैं 300 से ज्यादा योजनाएं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 17.5 लाख करोड़ रुपये सीधे लोगों के खातों में हस्तांतरित किए गए। 300 से ज्यादा योजनाएं डीबीटी का उपयोग कर रही हैं। 90 करोड़ भारतीय किसी न किसी रूप में या एलपीजी, राशन, चिकित्सा उपचार, छात्रवृत्ति, पेंशन या वेतन वितरण जैसे क्षेत्रों में लाभान्वित हो रहे हैं। इसके माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सीधे 1 लाख 35 हजार करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं। गेहूं की सरकारी खरीद के लिए 85 हजार करोड़ रुपये का भुगतान भी किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि 1 लाख 78 हजार करोड़ रुपये गलत हाथों में जाने से बच गए।

श्री मोदी ने कहा कि भारत में डिजिटल लेनदेनों के विकास से गरीब और वंचित, छोटे उद्यम, किसान और आदिवासी आबादी सशक्त हुई है। यह जुलाई में 6 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड 300 करोड़ यूपीआई लेनदेनों से महसूस किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना ने देश के बड़े शहरों और छोटे कस्बों में 23 लाख से ज्यादा रेहड़ी-पटरी वालों की मदद की है। इस महामारी के दौरान उनके बीच लगभग 2,300 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 6-7 वर्षों में देश में डिजिटल इंफ्रॉस्ट्रक्चर और डिजिटल लेन-देन के लिए किए गए कार्यों के प्रभाव को पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि खास तौर पर भारत में फिनटेक का बहुत व्यापक आधार तैयार हुआ है, जो यहां तक कि विकसित देशों में भी नहीं है। ■

क्या है डिजिटल भुगतान का नया साधन 'ई-रुपी'?

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2 अगस्त को कैशलेस और संपर्क रहित भुगतान के साधन के रूप में डिजिटल भुगतान समाधान 'ई-रुपी' का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने कहा कि देश में डिजिटल लेनदेन में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) को और अधिक प्रभावी बनाने में 'ई-रुपी' वाउचर एक बड़ी भूमिका निभायेगा और डिजिटल शासन व्यवस्था को एक नया आयाम देगा। आइए जानते है क्या है 'ई-रुपी':

'ई-रुपी' क्या है और यह कैसे काम करता है?

- 'ई-रुपी' मूल रूप से एक डिजिटल वाउचर है जो एक लाभार्थी को उसके फोन पर एसएमएस या क्यूआर कोड के रूप में मिलता है। यह एक प्रीपेड वाउचर है, जिसे वह किसी भी केंद्र पर, जो इसे स्वीकार करता है, जाकर उसका उपयोग कर सकता है।
- उदाहरण के लिए यदि सरकार अपने कर्मचारी का किसी निर्दिष्ट अस्पताल में विशेष उपचार का खर्च वहन करना चाहती है, तो वह एक भागीदार बैंक के माध्यम से निर्धारित राशि के लिए 'ई-रुपी' का वाउचर जारी कर सकेगी। कर्मचारी को उसके फीचर फोन/स्मार्ट फोन पर एक एसएमएस या एक क्यूआर कोड प्राप्त होगा। वह निर्दिष्ट अस्पताल में जाकर उसकी सेवाओं का लाभ उठायेगा और अपने फोन पर प्राप्त 'ई-रुपी' वाउचर से भुगतान कर सकेगा।
- इस प्रकार 'ई-रुपी' एक बार का संपर्क रहित, कैशलेस वाउचर-आधारित भुगतान का तरीका है जो उपयोगकर्ताओं को कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग तक पहुंचे बिना वाउचर भुनाने में मदद करता है।
- ई-रुपी को वैसी डिजिटल मुद्रा मानने का भ्रम नहीं होना चाहिए जिसे लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक विचार कर रहा है। इसकी बजाय 'ई-रुपी' एक व्यक्ति विशिष्ट, यहां तक कि उद्देश्य विशिष्ट डिजिटल वाउचर है।

'ई-रुपी' उपभोक्ता के लिए कैसे फायदेमंद है?

- 'ई-रुपी' के लिए लाभार्थी के पास बैंक खाता होना आवश्यक नहीं है, जो अन्य डिजिटल भुगतान माध्यमों की तुलना में इसकी एक प्रमुख विशिष्टता है। यह एक आसान, संपर्क रहित भुगतान पाने की दो-चरणीय प्रक्रिया सुनिश्चित करता है जिसमें व्यक्तिगत विवरण साझा करने की भी आवश्यकता नहीं होती है।
- एक अन्य लाभ यह भी है कि 'ई-रुपी' बुनियादी फोन पर भी संचालित होता है, इसलिए इसका उपयोग उन लोगों द्वारा भी किया जा सकता है जिनके पास स्मार्ट फोन नहीं है या उन जगहों पर जहां इंटरनेट कनेक्शन कमजोर है।

प्रायोजकों को 'ई-रुपी' से क्या लाभ हैं?

- प्रत्यक्ष-लाभ हस्तांतरण को मजबूत करने तथा इसे और अधिक पारदर्शी बनाने में 'ई-रुपी' एक प्रमुख भूमिका निभा सकेगा ऐसी आशा है। चूंकि, वाउचर को भौतिक रूप से जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इससे लागत की भी कुछ बचत होगी।

सेवा प्रदाताओं को क्या लाभ होंगे?

- 'ई-रुपी' प्रीपेड वाउचर होने के नाते सेवा प्रदाता को रीयल टाइम भुगतान का भरोसा देगा।

'ई-रुपी' किसने विकसित किया है?

- भारत में डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की देखरेख करने वाले नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए यह वाउचर-आधारित भुगतान प्रणाली 'ई-रुपी' लॉन्च की है।
- वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से इसे विकसित किया गया है।

कौन से बैंक 'ई-रुपी' जारी करते हैं?

- नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 'ई-रुपी' लेनदेन के लिए 11 बैंकों के साथ साझेदारी की है। ये बैंक हैं एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया।
- इसे लेने वाले ऐप्स हैं भारत पे, भीम बड़ौदा मर्चेंट पे, पाइन लैब्स, पीएनबी मर्चेंट पे और योनो एसबीआई मर्चेंट पे हैं।
- जल्द ही 'ई-रुपी' स्वीकार करने वाले और अधिक बैंकों तथा ऐप्स के इसमें शामिल होने की उम्मीद है।

अभी 'ई-रुपी' का उपयोग कहां किया जा सकता है?

- शुरुआत में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 1,600 से अधिक अस्पतालों के साथ करार किया है जहां 'ई-रुपी' को भुनाया अर्थात उससे भुगतान किया जा सकता है।
- विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में 'ई-रुपी' का उपयोग का आधार व्यापक होने की उम्मीद है। यहां तक कि निजी क्षेत्र भी इसका उपयोग अपने कर्मचारियों को लाभ देने के लिए कर सकेंगे। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग भी इसे 'बिजनेस-टू-बिजनेस' लेनदेन के लिए अपना सकेंगे। ■

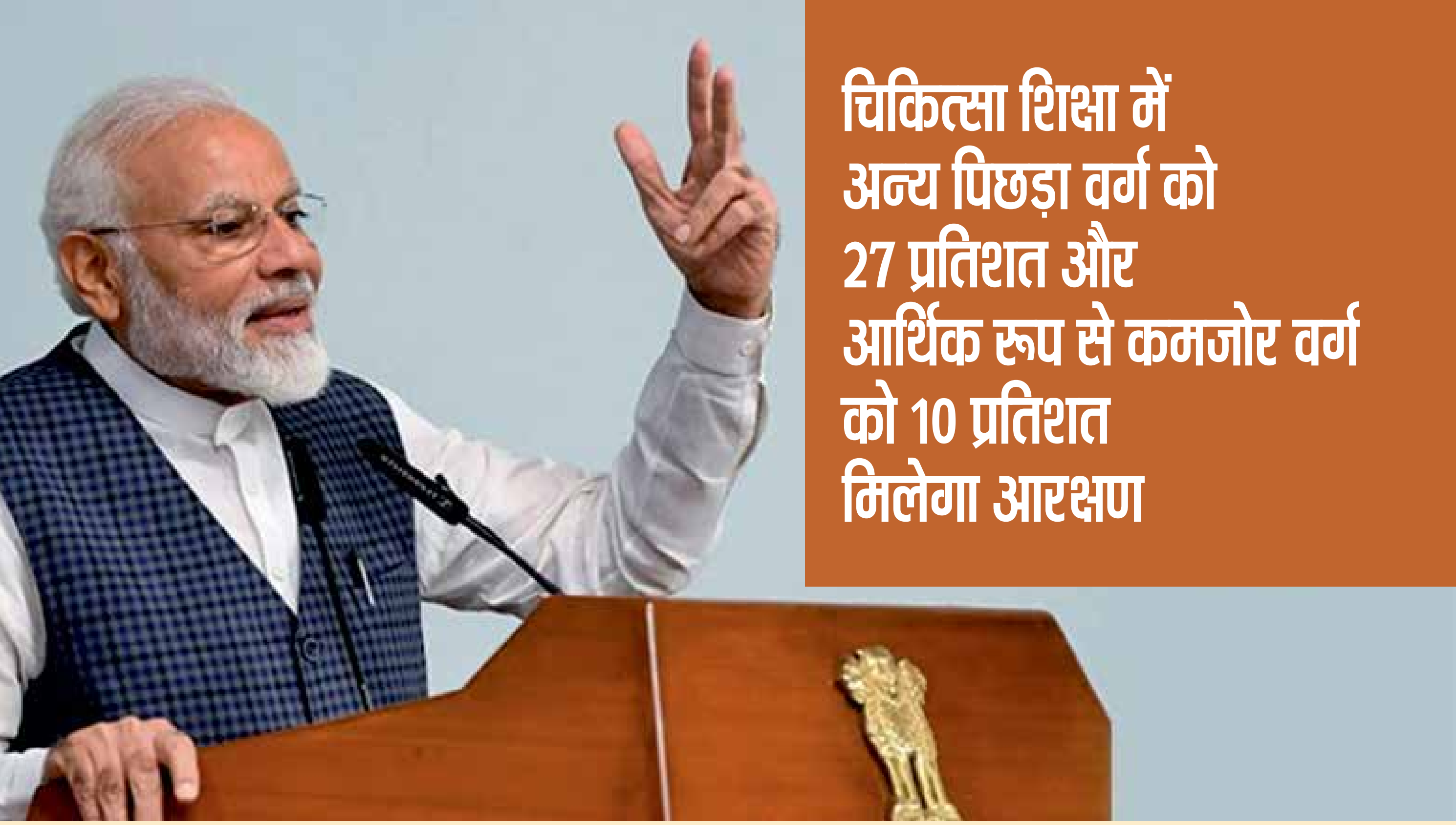

चिकित्सा शिक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत मिलेगा आरक्षण

गत 29 जुलाई, 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से स्नातक और स्नातकोत्तर मेडिकल/डेंटल कोर्स (एमबीबीएस/एमडी/एमएस/डिप्लोमा/बीडीएस/एमडीएस) के लिए अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) योजना में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उल्लेखनीय है कि श्री मोदी ने 26 जुलाई को हुई बैठक में संबंधित मंत्रालयों को लंबे समय से लंबित इस मुद्दे का एक प्रभावी समाधान प्रदान के निर्देश दिए थे। इस फैसले से हर साल लगभग 1500 ओबीसी विद्यार्थियों को एमबीबीएस में और 2500 ओबीसी विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर में तथा 550 ईडब्ल्यूएस विद्यार्थियों को एमबीबीएस में और लगभग 1000 ईडब्ल्यूएस विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर में लाभ मिलेगा।

'प्रधानमंत्री मोदीजी ने सामाजिक सद्भाव के माध्यम से वंचित तबकों के सपने को साकार किया है'

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव ने 31 जुलाई को पार्टी के नई दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय में आयोजित प्रेस-वार्ता को संबोधित किया और सामाजिक समरसता के सिद्धान्त को आधार मानकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा ओबीसी, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के कल्याण के लिए उठाये गए क़दमों की भूरि-भूरि सराहना की।

श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के मंत्र के साथ 'ईज ऑफ लिविंग' का विचार प्रतिपादित किया है ताकि भेदभाव से मुक्त समाज में पिछड़े लोगों को बुनियादी सुविधाएं शीघ्र और सस्ती दर पर उपलब्ध करायी जा सके। अब पिछड़ों, दलितों, शोषितों और वंचितों को भी लगने लगा है कि केंद्र में उनकी सरकार है और वास्तव में उनके लिए काम किया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्रीजी ने सामाजिक सद्भाव के माध्यम से वंचित तबकों के सपने को साकार किया है और उनमें नई आकांक्षाएं पैदा की हैं। मोदी सरकार की हर योजना, हर कार्यक्रम का केंद्र बिंदु गरीब, कमजोर, पिछड़ा तबका है। अंत्योदय प्रधानमंत्री का संकल्प है और समतामूलक एवं न्यायपूर्ण समाज की स्थापना उनका उद्देश्य।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार के साथ ही सामाजिक न्याय को भी प्राथमिकता दी है। 29 जुलाई, 2021 को ही प्रधानमंत्रीजी ने मेडिकल शिक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का

प्रधानमंत्री ने चिकित्सा पाठ्यक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के सरकार के फैसले की सराहना की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 29 जुलाई को वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से स्नातक और स्नातकोत्तर मेडिकल/डेंटल पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय कोटा योजना में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के सरकार के ऐतिहासिक फैसले की सराहना की।

श्री मोदी ने कई ट्वीट्स के माध्यम से कहा कि हमारी सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से स्नातक और स्नातकोत्तर मेडिकल/डेंटल पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय कोटा योजना में ओबीसी को 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का एक ऐतिहासिक फैसला किया है। इससे हर साल हजारों की संख्या में युवाओं को बेहतर अवसर हासिल करने और हमारे देश में सामाजिक न्याय का एक नया उदाहरण पेश करने में सहायता मिलेगी।

इस ऐतिहासिक फैसले पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 29 जुलाई को ट्वीट कर कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, जिसमें चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय कोटा योजना में ओबीसी को 27 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, इससे हजारों छात्र लाभान्वित होंगे।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 29 जुलाई को चिकित्सा पाठ्यक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के ऐतिहासिक फैसले के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सराहना की। अपने ट्वीट्स में श्री शाह ने कहा कि मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में स्नातक और स्नातकोत्तर (PG Medical/Dental courses) में अखिल भारतीय कोटा योजना में ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने के ऐतिहासिक निर्णय पर श्री नरेन्द्र मोदी का अभिनंदन करता हूं।

गृह मंत्री ने कहा कि बहुत समय से लंबित इस मांग को पूरा कर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए प्रति सरकार की कटिबद्धता को दर्शाया है। मोदी सरकार के इस निर्णय से लगभग 5550 छात्र लाभान्वित होंगे।

ऐतिहासिक फैसला किया। इसे वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से ही लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत एमबीबीएस, एमएस, बीडीएस, एमडीएस और डिप्लोमा में 5,550 छात्रों को फायदा मिलेगा। उनके इस एक निर्णय से हर साल एमबीबीएस में लगभग 1,500 ओबीसी और 550 ईडब्ल्यूएस छात्रों को प्रवेश मिल सकेगा। वहीं, मेडिकल के स्नातकोत्तर कोर्स में 2,500 ओबीसी छात्रों और करीब 1,000 ईडब्ल्यूएस छात्रों को प्रवेश का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी समाज और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के युवाओं को मेडिकल कॉलेज की पीजी और यूजी की पढ़ाई में आरक्षण का निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को हार्दिक बधाई देती है और उनका अभिनंदन करती है।

उन्होंने कहा कि ओबीसी समुदाय के कल्याण के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाये हैं। पिछड़ा वर्ग के आयोग को संवैधानिक दर्जा देने करने की मांग एक लंबे समय से चली आ रही थी। कांग्रेस की यूपीए सरकार के पिछले 10 वर्ष में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। ये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी हैं जिन्होंने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देकर पिछड़े वर्ग के लोगों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया।

विपक्ष पर हमला करते हुए श्री यादव ने कहा कि कांग्रेस को बताना चाहिए कि लंबे समय तक सत्ता में रहकर उसने ओबीसी के हितों के विषयों को क्यों रोके रखा? आर्थिक रूप से कमजोर तबके के 10% आरक्षण के लिए कांग्रेस ने क्यों नही कुछ किया? जब मोदी सरकार यह कर रही है तो कांग्रेस की स्थिति 'खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे' वाली होनी स्वाभाविक है।

श्री यादव ने कहा कि मोदी सरकार में पिछले 5 वर्षों में 179 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं। देश में अब 558 मेडिकल कॉलेज हैं। देश में यूजी की सीटों में 56% के करीब और पीजी की सीटों में 80% के करीब बढ़ोतरी की गई। इसका बहुत बड़ा फायदा ओबीसी, एससी, एसटी समुदाय को मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में दलित, पिछड़े, ओबीसी एवं महिलाओं को व्यापक प्रतिनिधित्व मिला है। वर्तमान में मोदी सरकार में 27 मंत्री ओबीसी समुदाय से हैं जबकि 20 एससी/एसटी समुदाय से हैं और 11 महिलाएं हैं। ओबीसी आरक्षण में 'क्रीमी लेयर' की आय सीमा भी बढ़ाई गई। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, जन-धन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो या अन्य योजनायें, हमारी सरकार की हर योजना में पिछड़े वर्ग, एससी, एसटी और महिलाओं को लाभ मिला है। एससी और ओबीसी वर्ग के छात्रों की फ्री-कोचिंग और प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए वार्षिक आय की पात्रता को बढ़ा दिया गया है। ओबीसी वर्ग के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति में भारी वृद्धि की गई। श्री यादव ने कहा कि पहली बार घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जातियों के लिए मोदी सरकार में एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया। बाबा साहब के सिद्धांतों को जमीन पर यदि किसी सरकार ने उतारा है तो वह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार है। ■

अन्य राज्यों में विवाह करने वाली जम्मू और कश्मीर की महिलाओं के पति अब प्राप्त कर सकते हैं 'डोमिसाइल सर्टिफिकेट'

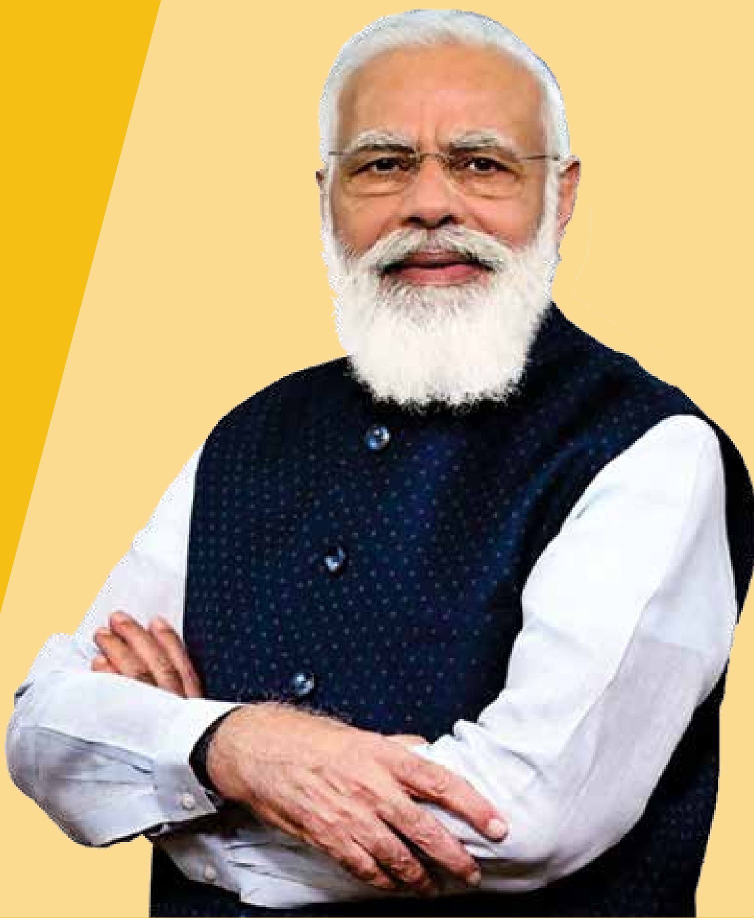

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने 'जम्मू और कश्मीर ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट (प्रक्रिया) नियम, 2020' में एक क्लॉज जोड़ा है, जिससे केंद्रशासित प्रदेश के बाहर विवाह करने वाली यहां की मूल महिला निवासी के पति को डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने की अनुमति मिलती है।

नए खंड के अनुसार संबंधित तहसीलदार को महिला द्वारा निवास प्रमाण-पत्र के साथ-साथ विवाह का वैध प्रमाण दिखाने पर उसके पति को अधिवास प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। उपायुक्त किसी भी शिकायत के मामले में अपीलीय प्राधिकारी है। इस आदेश ने जम्मू और कश्मीर सरकार में सभी स्तरों की नौकरियों के लिए अधिवास की स्थिति को भी संशोधित किया है, क्योंकि नए जोड़े गए खंड को जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा (विकेंद्रीकरण और भर्ती) अधिनियम के तहत भी लाया गया है।

21 जुलाई, 2021 को उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा के आदेश पर प्रशासन द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिससे जम्मू और कश्मीर की धारा 15 के साथ पढ़ा जाए, सिविल सेवा (विकेंद्रीकरण और भर्ती) अधिनियम 2010, सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि 'जम्मू और कश्मीर अधिवास अनुदान (प्रक्रिया) नियम 2020, के नियम 5 के उप नियम (1) में संलग्न तालिका में नया खंड जोड़ा जाएगा, क्रमांक/खंड 6' के बाद।

भाजपा महिला मोर्चा ने ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री को दिया धन्यवाद

भाजपा महिला मोर्चा ने इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया। अब जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की महिलाओं को डोमिसाइल अधिकारों का लाभ होगा, जिससे उनको दशकों से वंचित रखा गया था।

एक प्रेस बयान में भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती वानथी श्रीनिवासन ने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय महिला मोर्चा की ओर से इस दूरगामी निर्णय के लिए हम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं।

उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता-पूर्व के राजशाही-युग की नीति के अनुसार, जो केवल उन लोगों को स्थायी निवासी का दर्जा देती थी, जो 14 मई, 1954 को राज्य के निवासी थे, जिसे भारत के संविधान के अब निरस्त किए गए अनुच्छेद 35ए द्वारा संरक्षित किया गया था, उसको अब मोदी सरकार ने समाप्त कर दिया गया है। इससे पहले, केवल स्थायी निवासी ही पूर्ववर्ती राज्य सरकार में रोजगार के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षण के लिए, राज्य द्वारा संचालित व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश के लिए और राज्य में संपत्ति के अधिकार के पात्र थे। ■

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा की पहल

राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक प्रशिक्षण अभियान

कोविड महामारी की विभीषिका ने दुनिया के कई देशों को आक्रांत किया। इससे भारत भी अछूता नहीं रहा। कठिन चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत ने कोरोना को परास्त करने के लिए लड़ाई लड़ी, वह अपने आप में अभूतपूर्व है।

कोविड की पहली और दूसरी लहर के दौरान टेस्टिंग, वेंटिलेटर संचालन तथा अन्य सामान्य चिकित्सीय जानकारी के साथ-साथ प्रभावितों की मदद और मरीजों की अस्पतालों में भर्ती में मदद अन्य स्वास्थ्य संबंधी सहायता के लिए बड़े पैमाने पर हेल्थ वालंटियर्स की आवश्यकता महसूस की गई।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने विगत 6 और 7 जून, 2021 को 'सेवा ही संगठन' कार्यक्रम की समीक्षा को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाई थी जिसमें उन्होंने हेल्थ वालंटियर्स की जरूरत पर विस्तार से चर्चा की थी। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने उनकी दूरदर्शी पहल पर 'अपना बूथ, कोरोना मुक्त' अभियान को अपने हाथ में लिया था। देश को कोरोना मुक्त बनाने के लिए श्री नड्डा ने इस बैठक में यह तय किया कि देश भर में स्वास्थ्य स्वयंसेवक तैयार किये जाएंगे। स्वास्थ्य स्वयंसेवक तैयार करने के पीछे उनकी यह सोच रही है कि इससे न केवल कोविड से मुक्ति पाने में देश को मदद मिलेगी बल्कि स्वास्थ्य वालंटियर्स की एक ऐसी फ़ौज भी तैयार हो जाएगी जो आनेवाले कई वर्षों तक देश को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से निजात दिलाने में प्रभावी भूमिका भी निभाएगी।

इस विजन को जमीन पर उतारने के लिए 28 जुलाई 2021 को श्री नड्डा ने पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय में हेल्थ वालंटियर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान' का श्रीगणेश किया। इस कार्यक्रम का टैगलाइन है - "यथा यथाय तुष्यत तथा संतोषयेत् तुम्" अर्थात् जिसकी हम सेवा करते हैं, उसका सुख ही हमारा संतोष है। यही पंक्ति अपने-आप में भारतीय जनता पार्टी की सेवा भावना को रेखांकित करने के लिए काफी है। इसी भावना से, गरीबों के प्रति इसी सम-भाव और मम-भाव से, हमारे कार्यकर्ताओं ने इतने कठिन समय में 'सेवा ही संगठन' का इतना बड़ा अभियान चलाया है।

श्री नड्डा ने पार्टी के लिए लक्ष्य निर्धारित किया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के जरिये हमें देश के दो लाख गांवों तक पहुंचना है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने 4 लाख हेल्थ वालंटियर्स को प्रशिक्षित करने का बीड़ा उठाया है। अब तक लगभग 1,03,872 से अधिक वालंटियर्स ने इस कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत हर बूथ पर भाजपा दो स्वास्थ्य स्वयंसेवक (एक पुरुष, एक महिला) तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित कर चल रही है जो अपने-अपने बूथ के लोगों का कोविड देखभाल करेंगे। उनके पास ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर, एंटीबॉडी बूस्टर और रैपिड एंटीजेन टेस्ट किट भी उपलब्ध होंगे। वे न केवल लोगों को कोविड के प्रति जागरुक करेंगे बल्कि उन्हें कोविड से लड़ने में भी मदद करेंगे।

आगामी 30 अगस्त 2021 तक प्रदेश स्तर और जिला स्तर से लेकर मंडल स्तर तक भारतीय जनता पार्टी इस प्रशिक्षण अभियान को पूरा कर लेगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में बताया जा रहा है कि एक स्वास्थ्य स्वयंसेवक की भूमिका क्या होगी, उनके क्या कार्य हैं, कोविड अनुकूल व्यवहार क्या हैं, क्या-क्या रोग प्रतिरोधक तरीके हो सकते हैं और उन्हें किस तरह से आम जन की मदद करनी है। एक स्वास्थ्य स्वयंसेवक लोगों को कोविड से बचाव की जानकारी देने के साथ-साथ प्राथमिक लक्षणों की जांच में भी मदद करेंगे और कब रोगी को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ेगी, ये भी बताएंगे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने में भी सहयोग देंगे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने दुनिया का सबसे बड़ा सेवा कार्यक्रम 'सेवा ही संगठन' अभियान चलाया था। कोविड की पहली और दूसरी लहर के दौरान भारतीय जनता पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता ने 'सेवा ही संगठन' के तहत अपनी जान जोखिम में डाल कर मानवता की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया। कोविड संक्रमण के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने 50-60 करोड़ फूड पैकेट्स वितरित किये, लगभग 25 करोड़ फेस मास्क और 20 करोड़ सेनिटाइजर वितरित किये गए।

पिछले डेढ़ साल से भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर देश की लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टियां या तो क्वारंटाइन में हैं या आइसोलेशन में। ये जनता के बीच नहीं, केवल ट्विटर और प्रेस कांफ्रेंस में दिखते हैं। यह केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है जो जनता के साथ मिल कर उनकी भलाई के लिए काम कर रही है। ■

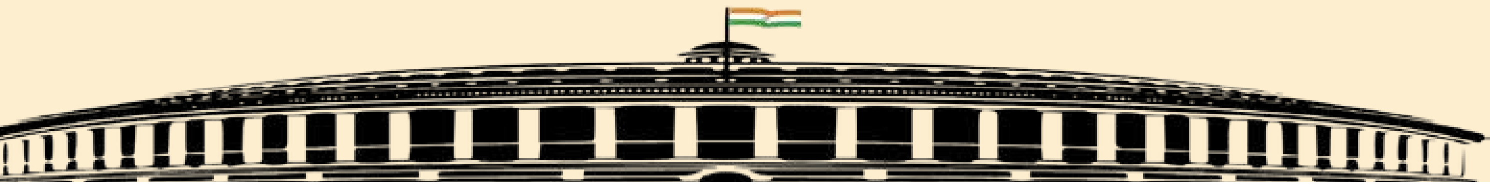

संसद ने ऐतिहासिक 'अंतर्देशीय पोत विधेयक, 2021' पारित किया

अंतर्देशीय जल परिवहन की क्षमता का दोहन करने और इसे कार्गो एवं यात्रियों की आवाजाही के लिए भीड़भाड़ वाली सड़क और रेल नेटवर्क के समांतर परिवहन के एक पूरक और पर्यावरण के अनुकूल साधन के रूप में बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कई पहल किए हैं और 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग के तौर पर घोषित किया है

गत दो अगस्त को संसद ने 'अंतर्देशीय पोत विधेयक, 2021' को पारित किया। इस विधेयक का उद्देश्य 100 साल से अधिक पुराने अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 1917 (1917 का 1) को प्रतिस्थापित करना, अंतर्देशीय जल परिवहन के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत करना, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण को साकार करना, विधायी ढांचे को उपयोगकर्ताओं के अनुकूल बनाना और व्यापार करने की आसान प्रक्रिया को बढ़ावा देना है। केन्द्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस विधेयक को दो अगस्त को राज्यसभा में पेश किया। अब इस विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।

श्री सोनोवाल ने कहा कि यह पहल औपनिवेशिक कानूनों को निरस्त करके उन्हें समुद्री क्षेत्र की आधुनिक एवं समकालीन जरूरतों को पूरा करने वाले और उनके विकास से जुड़े कानूनों से प्रतिस्थापित करने की दिशा में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा अपनाए गए सक्रिय दृष्टिकोण का एक हिस्सा है। उन्होंने यह भी कहा कि नियमों और विनियमों का एक समान कार्यान्वयन अंतर्देशीय जहाजों द्वारा अंतर्देशीय जलमार्गों का उपयोग करते हुए निर्बाध, सुरक्षित और किफायती व्यापार एवं परिवहन को सुनिश्चित करेगा।

नियमों और विनियमों का एक समान कार्यान्वयन अंतर्देशीय जहाजों द्वारा अंतर्देशीय जलमार्गों का उपयोग करते हुए निर्बाध, सुरक्षित और किफायती व्यापार एवं परिवहन को सुनिश्चित करेगा

पृष्ठभूमि

श्री सोनोवाल ने बताया कि अंतर्देशीय जल परिवहन की क्षमता का दोहन करने और इसे कार्गो एवं यात्रियों की आवाजाही के लिए भीड़भाड़ वाली सड़क और रेल नेटवर्क के समांतर परिवहन के एक पूरक और पर्यावरण के अनुकूल साधन के रूप में बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई पहल किए हैं और 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग के तौर पर घोषित किया है।

1917 के अंतर्देशीय पोत अधिनियम की परिकल्पना सीमित कार्यान्वयन और उद्देश्यों वाले एक शुद्ध समेकित कानून के रूप में की गई थी। इस अधिनियम में कई संशोधन किए गए और पिछले महत्वपूर्ण संशोधन 1977 और 2007 में किए गए थे। इस अधिनियम में राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के भीतर यांत्रिक रूप से चालित जहाजों के प्रतिबंधात्मक आवाजाही, अनुमोदन की आवश्यकता, सीमित कार्यान्वयन और प्रमाण-पत्र की वैधता, असमान मानकों एवं विनियमों से जुड़े प्रावधान शामिल थे, जिनके राज्य दर राज्य अलग-अलग होने के कारण विभिन्न राज्यों के बीच निर्बाध नौचालन और इस क्षेत्र के विकास में बाधाएं और अड़चनें आईं।

केन्द्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि एक ऐसी नई कानूनी व्यवस्था की जरूरत थी, जोकि भविष्य के तकनीकी विकास के अनुकूल और अनुरूप हो, व्यापार और परिवहन की वर्तमान एवं भविष्य की संभावनाओं और अंतर्देशीय जहाजों द्वारा सुरक्षित नौचालन को सुविधाजनक बनाने में सक्षम हो।

लाभ

नया अधिनियम अंतर्देशीय जहाजों के सामंजस्यपूर्ण एवं प्रभावी विनियमन और विभिन्न राज्यों के बीच उनके निर्बाध और सुरक्षित परिचालन की सुविधा प्रदान करेगा। इसके प्रमुख लाभ निम्न हैं:

- अंतर्देशीय जलमार्गों का उपयोग करते हुए निर्बाध, सुरक्षित और किफायती व्यापार एवं परिवहन सुनिश्चित करने के लिए नियमों और विनियमों का एक समान कार्यान्वयन।
- यांत्रिक रूप से चालित जहाजों के वर्गीकरण और वर्गीकरण के मानकों का निर्धारण, जहाजों के पंजीकरण से जुड़े मानक और प्रक्रियाएं; केन्द्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी के जहाजों की पहचान एवं उनके वर्गीकरण से जुड़े मानक आदि और राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुपालन से जुड़े प्रावधानों का कार्यान्वयन।
- संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्थापित प्राधिकरणों की स्थिति को संरक्षित करना और इस प्रकार प्रस्तावित कानून के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना।
- डिजिटल इंडिया अभियान की भावना को आत्मसात करते हुए एक केंद्रीय डेटाबेस/पंजीकरण के लिए ई-पोर्टल/क्रू डेटाबेस का प्रावधान।
- नौचालन की सुरक्षा, जीवन एवं कार्गो की सुरक्षा, पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, व्यापार की स्वस्थ प्रथाओं की व्यवस्था करने, कल्याण कोष का गठन, प्रशासनिक तंत्र की पारदर्शिता एवं जवाबदेही, सक्षम एवं कुशल श्रमशक्ति के प्रशिक्षण और विकास को सुनिश्चित करने के लिए उच्च मानकों का निर्धारण करना।
- हताहतों और जांच से संबंधित उन्नत प्रावधान। ■

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 25 जुलाई, 2021 को 'मन की बात' कार्यक्रम में दिए गए संबोधन का संपादित पाठ

जब भी लीक से हटकर कोशिशें हुईं, मानवता के लिए नये द्वार खुले: नरेन्द्र मोदी

गत 25 जुलाई को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के विभिन्न हिस्सों में कृषि क्षेत्र में किए जा रहे अभिनव प्रयोगों और कृषि अवशेषों को नए रूप में पेश कर आमदनी बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जब भी लीक से हटकर कोशिशें हुईं, मानवता के लिए नये द्वार खुले और एक नये युग की शुरुआत हुई है।

आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के ताजा संस्करण में देशवासियों से संवाद करते हुए श्री मोदी ने कृषि क्षेत्र में हो रहे अभिनव प्रयोगों की जानकारी साझा की और कहा कि ऐसे उदाहरण जीवन में कुछ नया करने की प्रेरणा बन जाते हैं।

इस कड़ी में उन्होंने मणिपुर के उखरुल में हो रही सेब की खेती का उल्लेख किया और कहा कि अभी तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर ही इस फल के उत्पादन के लिए जाने जाते थे लेकिन अब इसमें मणिपुर का भी नाम जुड़ गया है।

उन्होंने बताया कि कुछ नया करने के जज्बे के चलते मणिपुर के कुछ युवाओं ने यह कारनामा कर दिखाया। उन्होंने कहा कि पेशे से वैमानिक इंजीनियर (एयरोनॉटिक इंजीनियर) टीएस रिंगफामी योंग ने हिमाचल प्रदेश जाकर सेब उत्पादन का प्रशिक्षण लिया और उन्होंने अपनी पत्नी टीएस एंजल के साथ मिलकर मणिपुर में सेब की पैदावार की। इसी प्रकार दिल्ली में नौकरी छोड़ अवुन्गशी शिमरे ऑगस्टीना ने भी सेब की खेती का रुख किया।

श्री मोदी कहा कि मणिपुर में आज ऐसे कई सेब उत्पादक हैं, जिन्होंने कुछ अलग और नया करके दिखाया है। प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा के उनकोटी में बेर की खेती करने वाले युवा बिक्रमजीत चकमा का जिक्र किया और कहा कि इससे न सिर्फ उन्होंने 'काफी मुनाफा' कमाया बल्कि अब वह लोगों को बेर की खेती करने के लिए प्रेरित भी कर रहे है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आई है और उसकी ओर से कई विशेष नर्सरी बनाई गई हैं ताकि बेर की खेती से जुड़े लोगों की मांग पूरी की जा सके।

श्री मोदी कहा कि खेती में नवोन्मेष हो रहे हैं तो खेती के उपोत्पाद में भी रचनात्मकता देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किए गए ऐसे ही एक प्रयास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वहां महिलाओं ने केले के बेकार तनों से फाइबर बनाने का प्रशिक्षण देने का काम शुरु किया। उन्होंने कहा इस फाइबर से हाथों का बैग, चटाई, दरी और न जाने कितनी ही चीजें बनाई जाती हैं।

उन्होंने कहा कि इससे एक तो फसल के कचरे का इस्तेमाल शुरू हो गया, वहीं दूसरी तरफ गांव में रहने वाली हमारी बहनों-बेटियों को आय का एक और साधन मिल गया। केले की फसल के बाद आमतौर पर किसानों को इसके तने को फेंकने के लिए अलग से खर्च करना पड़ता था। अब उनके यह पैसे भी बच जाते है यानी आम के आम, गुठलियों के दाम ये कहावत यहां बिल्कुल सटीक बैठती है।

श्री मोदी ने इस क्रम में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ और दक्षिण कन्नड़ जिलों में केले के आटे से डोसा और गुलाब जामुन जैसे स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाने का जिक्र किया।

उन्होंने कहा कि यह शुरुआत भी कोरोना काल में ही हुई है। यहां की महिलाओं ने न सिर्फ केले के आटे से डोसा, गुलाब जामुन जैसी चीजें बनाई बल्कि इनकी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा भी किया। जब ज्यादा लोगों को केले के आटे के बारे में पता चला तो उसकी मांग भी बढ़ी और इन महिलाओं की आमदनी भी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे उदाहरण जीवन में कुछ नया करने की प्रेरणा बन जाते हैं और ऐसा करने वाले लोग आपके आस-पास भी होंगे। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वह समय निकलकर बच्चों के साथ ऐसे प्रयासों को देखने जाएं और अवसर मिले तो खुद भी ऐसा कुछ कर दिखाएं। ■

‘खेल रत्न पुरस्कार’ को अब से कहा जाएगा ‘मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार’

गत छह अगस्त को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि उन्हें देशभर के नागरिकों से ‘खेल रत्न पुरस्कार’ का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने के लिए अनगिनत अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए ‘खेल रत्न पुरस्कार’ को अब से ‘मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार’ कहा जाएगा।

श्री मोदी ने यह भी कहा कि मेजर ध्यानचंद भारत के उन अग्रणी खिलाड़ियों में से एक थे जिन्होंने भारत के सम्मान और गौरव को नए शिखर पर पहुंचा दिया था। अतः यह बिल्कुल उचित है कि हमारे देश का सर्वोच्च खेल सम्मान उन्हीं के नाम पर रखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा है कि ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रयासों से हम सभी अभिभूत हैं। विशेषकर हॉकी में हमारे बेटे-बेटियों ने जो इच्छाशक्ति दिखाई है, जीत के प्रति जो ललक दिखाई है, वो वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने प्रधानमंत्री के निर्णय का स्वागत करते हुए ट्वीट कर कहा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने घोषणा की है कि अब से खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। 'हॉकी के जादूगर' के नाम पर सर्वोच्च खेल सम्मान का नाम रखना एक स्वागतयोग्य निर्णय है और राष्ट्र इसे स्वीकार करता है।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के फ़ैसले का स्वागत किया। अपने ट्वीट्स में श्री शाह ने कहा कि देश के सर्वोच्च खेल सम्मान 'खेल रत्न पुरस्कार' को देश के महानतम खिलाड़ी मेजर ध्यान चंदजी के नाम पर रखना उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। यह खेल जगत से जुड़े हर व्यक्ति के लिए एक गर्व का निर्णय है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का सभी देशवासियों की ओर से अभिनंदन करता हूं। ■

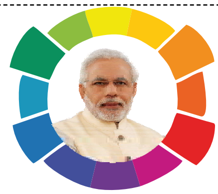

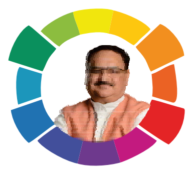

BECOME PART OF A VIBRANT IDEOLOGICAL MOVEMENT

BECOME PROUD MEMBER OF ‘KAMAL SANDESH’

SUBSCRIPTION DETAILS

Name : ....

Address : ....

.... Pin : ....

Phone : .... Mobile : (1)................................ (2)...............................

E-mail : ....

SUBSCRIPTION TYPE	One Year	₹350/-	☐	Life Time (English or Hindi)	₹3000/-	☐
	Three Years	₹1000/-	☐	Life Time (English+Hindi)	₹5000/-	☐

(DETAIL OF THE PAYMENT)

Cheque/Draft No. :............................. Date :....................... Bank : ....

Note : * DD/Cheque will be made in favour of "**Kamal Sandesh**"

* Money order and Cash accepted with details

(Subscriber's Signature)

KAMAL SANDESH

SEND YOUR DD/CHEQUE ON THIS ADDRESS

Dr. Mookerji Smruti Nyas, PP-66, Subramania Bharati Marg, New Delhi-110003

Ph.: 011-23381428 **Fax:** 011-23387887 **E-mail:** kamalsandesh@yahoo.co.in

KAMAL SANDESH - DEDICATED TO NATIONAL CAUSE

नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के लाभार्थियों से बातचीत करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विदेशों में भारतीय मिशनों के प्रमुखों और व्यापार एवं वाणिज्य क्षेत्र के हितधारकों के साथ बातचीत करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रथम वर्षगांठ पर शैक्षिक समुदाय को संबोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कमल संदेश
अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध
लॉग इन करें:
www.kamalsandesh.org
राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh
kamal.sandesh
@KamalSandesh
KamalSandeshLive

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली "रजिस्टर्ड"
36 पृष्ठ कवर सहित
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2021-23
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2021-23

प्रधानमंत्री की टोक्यो 2020 में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय दल को बधाई

"मैं खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय दल को बधाई देता हूं। उन्होंने बेहतरीन कौशल, टीमवर्क और समर्पण का परिचय दिया। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला हर एथलीट चैंपियन है।"

\- **नरेन्द्र मोदी**
प्रधानमंत्री

छायाकार: अजय कुमार सिंह